द शूटर

सूरजपुर जिले से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

प्रधान संपादक- रूपेश दुबे: 9826169678
संपादक- प्रवीण दुबे: 9165083700

वर्ष-14 अंक-168 | प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर छ.ग. से प्रकाशित | बुधवार 05 अगस्त 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य- 2 रूपये

बेटे को खोने का गम कम नहीं हुआ, अब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर-दर भटक रही मां

*** दो माह बाद भी नहीं मिला जरूरी दस्तावेज, हमर उत्थान सेवा समिति ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल**

सूरजपुर/प्रेमनगर, 04 अगस्त 2026 द शूटर।
सड़क हादसे में अपने 22 वर्षीय बेटे को खो चुकी एक मां की पीड़ा उस दिन खत्म नहीं हुई, जिस दिन बेटे की चिता जली थी। बीते दो माह से अधिक समय से वह अपने बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। हर बार उसे आश्वासन तो मिलता है, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं। नतीजा यह है कि परिवार बीमा दावा, शासकीय सहायता और अन्य आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब यह मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लगा है। पीड़ित मां ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) से शिकायत कर न्याय की मांग की है, जबकि सामाजिक संगठन हमर उत्थान सेवा समिति ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रेमनगर विकासखंड के ग्राम बकिरमा निवासी श्रीमती उर्मिला साहू ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके 22 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय सुजल साहू की 30 मई 2026 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई थी। हादसे के तुरंत बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर लाया गया, जहां इलाज के दौरान अंदरूनी चोटें अधिक होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन 31 मई को अस्पताल में डॉ. साधना

सिंह द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। उर्मिला साहू का कहना है कि वह कई बार अस्पताल और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा चुकी हैं। हर बार उन्हें अलग-अलग कार्यालय भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में बीमा राशि का दावा नहीं हो पा रहा है, न ही शासकीय सहायता योजनाओं का लाभ मिल रहा है। एक ओर बेटे के बिछड़ने का गहरा दुख है, तो दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था की उदासीनता उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है।इधर, हमर उत्थान सेवा समिति ने पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि जिस मां ने अपना जवान बेटा खोया हो, उसे एक आवश्यक दस्तावेज के लिए महीनों तक भटकाना किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के लिए शर्मनाक स्थिति है। समिति ने आरोप लगाया कि यदि संबंधित अधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं है और उन्हें स्वयं नियमों व सर्कुलर देखने की बात कहनी पड़ रही है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है।

समिति ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा लापरवाही के आरोपों को देखते हुए संबंधित बीएमओ के विरुद्ध जांच की मांग की है। कुलमिलाकर यह मामला केवल एक परिवार की परेशानी भर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल है, जहां एक मां को अपने बेटे के निधन का प्रमाण पाने के लिए भी महीनों तक भटकना पड़ रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस शिकायत पर कितनी संवेदनशीलता और तत्परता से कार्रवाई करता है।

राहगीरों पर पेड़ और मिट्टी गिरने का डर,लोक निर्माण विभाग ने वन विभाग को लिखा पत्र

*** प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में गोटगांव के पास की स्थिति,सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर पेड़ हटवाने की कही बात**

प्रतापपुर/द शूटर।
प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग में गोटगांव के पास सड़क के दोनों किनारे में मिट्टी कटाव के कारण मिट्टी और पेड़ के राहगीरों पर गिरने का डर हमेशा बना रहता है।स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर ने सामाजिक कार्यकर्ता की पहल पर वन विभाग को पत्र लिखा है।
उल्लेखनीय है कि कुछ साल पहले जब इस सड़क का नवनिर्माण हुआ था तब सड़क विकास निगम ने दोनों ओर मिट्टी काटी थी ताकि सड़क चौड़ी हो सके।इसके बाद से यहां नियमित मिट्टी कटाव बारिश के दिनों में होता है,मिट्टी कटने से पेड़ एकदम किनारे आ गए हैं और जड़ें बाहर की

ओर दिखने लगी हैं।मिट्टी बड़ी मात्रा में हमेशा गिरती है और पेड़ों के गिरने का डर भी बना रहता है।स्थिति को देखते हुए प्रतापपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मित्तल ने मामला उठाते हुए पीडब्ल्यूडी के ईई वीरेंद्र चौधरी से बात कर स्थिति से अवगत कराया था।इसके बाद सब इंजीनियर पल्लवी दुबे ने स्थल का निरीक्षण कर ईई को स्थिति से अवगत कराया था।अब ईई ने वन विभाग के रेंजर को पत्र लिखा है क्योंकि जगह वन भूमि है।पत्र में उन्होंने लिखा है कि अम्बिकापुर-प्रतापपुर मार्ग महत्वपूर्ण जिला मार्ग है,मार्ग के कि.मी. 37/4 गोटगवां में दोनों तरफ पहाड़ होने के कारण वर्षाऋतु में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिट्टी का कटाव हो रहा है। जिसके कारण दोनों किनारे में स्थित पेड़ गिरने कि स्थिति में है जिससे आवागमन बाधित एवं कोई भी हादसा होने की संभावना है। इसलिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थल निरीक्षण कर पेड़ हटवाने की आवश्यक कार्यवाही करें।

NMEO योजना से किसान ने एक एकड़ में लगाई मूंगफली, बेहतर उत्पादन से बढ़ी आमदनी

अम्बिकापुर 04 अगस्त 2026/
कृषि विभाग की राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम एवं तिलहन (NMEO) योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज एवं तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सकारात्मक परिणाम अब जिले के किसानों के खेतों में दिखाई देने लगा है। सरगुजा जिले के ग्राम ईरगवां निवासी किसान बेसाहू राम पिता रामप्रसाद एक्का ने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर योजना का लाभ लिया। उन्हें NMEO योजना के अंतर्गत 40 किलोग्राम उन्नत किस्म का मूंगफली बीज उपलब्ध कराया गया, जिसे उन्होंने एक एकड़ कृषि भूमि में बोया।
किसान ने बताया कि ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी के तकनीकी मार्गदर्शन में खेत की तैयारी, बुवाई एवं फसल प्रबंधन किया गया। वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के कारण बीज का अंकुरण बेहतर हुआ है तथा पौधों की बढ़वार भी अच्छी है। फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष मूंगफली के अच्छे उत्पादन की संभावना है, जिससे अच्छी आमदनी होगी।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठटएड योजना के माध्यम से किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, आधुनिक कृषि तकनीक तथा समय-समय पर तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इससे तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे विभागीय योजनाओं का लाभ लेकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकें।

15 दिनों से जियो नेटवर्क ध्वस्त, इंटरनेट सेवा ठप; आधा दर्जन गांवों का जनजीवन प्रभावित, 5जी टावर की उठी मांग

*** महुली का एकमात्र 4जी टावर जवाब दे गया, सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान तक हुए प्रभावित**

ओड़गी, 04 अगस्त 2026,
द शूटर। आज जब गांव-गांव तक डिजिटल सेवाओं के विस्तार की बात की जा रही है, वहीं सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के कई गांव पिछले 15 दिनों से संचार व्यवस्था की बदहाली झेलने को मजबूर हैं। महुली स्थित जियो के एकमात्र 4जी मोबाइल टावर में आई तकनीकी खराबी ने हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के बीच इंटरनेट सेवा लगभग ठप हो जाने से लोगों का धैर्य भी अब जवाब देने लगा है।महुली, कोल्हुआ, खोहीर, बैजनपाठ, कछवारी, जुडवनिया सहित आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों में मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल तो किसी तरह दिखाई देता है, लेकिन इंटरनेट सेवा लगभग बंद पड़ी है। कॉलिंग भी बाधित रहती है और मोबाइल डेटा नहीं चलने से सरकारी कार्यों से लेकर निजी जरूरतों तक हर काम प्रभावित हो रहा है।
सबसे अधिक परेशानी

शासकीय कार्यालयों, उचित मूल्य दुकानों, लोक सेवा केंद्रों, बैंकिंग सेवाओं, ऑनलाइन भुगतान, विद्यार्थियों की पढ़ाई और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में सामने आ रही है। डिजिटल माध्यम पर निर्भर नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
लोक सेवा केंद्र संचालक कमलकांत जायसवाल ने बताया कि इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन, आधार संबंधी सेवाएं तथा अन्य शासकीय कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें बार-बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
वहीं लोक सेवा केंद्र संचालक जितेंद्र साकेत ने जियो कंपनी से तत्काल नेटवर्क सुधार की मांग करते हुए कहा कि केवल अस्थायी मरम्मत से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए महुली के वर्तमान 4जी टावर को 5जी तकनीक में अपग्रेड किया जाना चाहिए, ताकि आसपास के सभी गांवों को बेहतर नेटवर्क और तेज इंटरनेट सुविधा मिल सके।ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में यदि लगातार दो सप्ताह तक इंटरनेट सेवा ठप रहे तो यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आम जनजीवन पर सीधा प्रभाव डालने वाली गंभीर स्थिति है। उन्होंने जियो कंपनी और संबंधित अधिकारियों से महुली टावर की तत्काल तकनीकी जांच कर नेटवर्क एवं इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी सामूहिक रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होंगे।

टीकाकरण में फर्जी आंकड़ों का खेल:शिकायत के बाद जांच शुरू

*** 2023 - 24 में 0 से 1 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर सूरजपुर जिला के साथ पूरे प्रदेश में हुई थी जांच की मांग**

प्रतापपुर/द शूटर।
टीकाकरण में फर्जी आंकड़ों के खेल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में हुई शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।वर्ष 2023 - 24 में 0 से 1 साल के बच्चों को हुए टीकाकरण को लेकर सूरजपुर जिले के साथ पूरे प्रदेश में जांच की मांग हुई थी।शिकायत स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास से मिले आंकड़ों में अंतर के आधार पर की गई थी।गौरतलब है कि सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के बैजनपाठ सहित अन्य गांवों में टीकाकरण का कार्य नहीं होता था जिसके बाद यह संभावना व्यक्त की गई थी कि पूरे जिले में यही स्थिति होगी और बिना टीकाकरण के ही शासन को फर्जी आंकड़े भेजे जाते होंगें।
इस सम्भावना के बाद प्रतापपुर के आरटीआई कार्यकर्ता राकेश मित्तल ने स्वास्थ्य विभाग सूरजपुर जिले से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 0 से 1 साल तक बच्चों के टीकाकरण को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी।इसी दरमियान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी जिला कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी और जब दोनों विभागों से मिली संख्या का मिलान किया गया तो दोनों की संख्या में काफी अंतर सामने आया।
आरटीआई कार्यकर्ता ने बताया कि दोनों विभागों से मिली संख्या के आधार पर यह तय हो गया था कि जितने बच्चों ने जिले के विभिन्न विकासखंडों में जन्म लिया,उससे कहीं ज्यादा बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगाया गया है,अर्थात शासन को भेजे गए आंकड़े फर्जी हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद टीकाकरण में फर्जी आंकड़ों की शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय,केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय छत्तीसगढ़ को मामले की शिकायत की थी और साक्ष्य के रूप में आंकड़ों से संबंधित दोनों विभागों से मिले दस्तावेज दिए थे। शिकायत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को जांच के लिए लिखा था।जांच की स्थिति को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया तो जांच की बातें सामने आई हैं।
सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने सूरजपुर जिले से बच्चों की सूची के साथ पूरी जानकारी मांगी है।

प्रदेश कार्यालय से टीकाकरण के टारगेट पर सवाल.....

राकेश मित्तल ने अपनी शिकायत में इस बात पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की थी कि जब बच्चों ने जन्म ही नहीं लिया है तो 0 से 1 साल के बच्चों का एक निर्धारित आंकड़ा बता टीकाकरण के लिए प्रदेश कार्यालय से टारगेट कैसे दिया जा सकता है।यह टारगेट भी वास्तविक बच्चों की संख्या से बहुत ज्यादा था।जैसे भैयाथान को टारगेट 4601 का दिया गया था और लक्ष्य प्राप्ति 91.22 प्रतिशत थी।इसी तरह ओडगी ब्लॉक को 3322 का लक्ष्य और प्राप्ति 90.90 प्रतिशत,प्रतापपुर 4926 का लक्ष्य और प्राप्ति 85.08 प्रतिशत,प्रेमनगर 2820 और लक्ष्य प्राप्ति 90.71,रामानुजनगर को 4601 और लक्ष्य प्राप्ति 93 प्रतिशत तथा सूरजपुर ब्लॉक को 7069 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य तथा प्राप्ति 93.78 प्रतिशत था।

स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस के आंकड़ों के साथ अंतर की स्थिति..

स्वास्थ्य विभाग से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 0 से 1 साल तक बच्चों के टीकाकरण की जो संख्या मिली थी उसके अनुसार भैयाथान ब्लाक में 4197,ओडगी में 3053,प्रतापपुर में 4191,प्रेमनगर में 2558,रामानुजनगर में 4279 तथा सूरजपुर ब्लाक में इनकी संख्या 6629 थी।महिला बाल विकास विभाग से जो जानकारी मिली उसके अनुसार प्रेमनगर परियोजना में बच्चों की संख्या 1020,भैयाथान में 1485,प्रतापपुर में 3458,ओडगी में 1840,रामानुजनगर में 2716 तथा सूरजपुर परियोजना और सिलफिली परियोजना मिलाकर सूरजपुर ब्लाक में 4748 संख्या थी।दोनों विभागों से जो आंकड़े मिले थे उनके अनुसार प्रतापपुर में 733 बच्चों का अंतर है।इसी तरह ओडगी में 1213,भैयाथान में 2712,प्रेमनगर में 1538,रामानुजनगर में 1583 तथा सूरजपुर ब्लाक में 1881 का अंतर था।

विभाग ने खुद ही दी थी कम बच्चों की सूची...

विभाग ने आरटीआई के तहत बच्चों के नाम की जो सूची दी थी उसमें भी यह स्पष्ट है कि आंकड़े फर्जी थी।इसके अनुसार भैयाथान में 1333 बच्चे कम थे,प्रेमनगर में 781,रामानुजनगर में 1177,प्रतापपुर में 100 तथा ओडगी में 126 बच्चे कम हैं,सूरजपुर ब्लॉक में इन्होंने 287 बच्चों की संख्या ज्यादा बताई थी।

कोरिया में सुशासन, रोजगार और कौशल विकास पर कलेक्टर का फोकस, अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

बैकुण्ठपुर। जिले में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने, रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने तथा जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण को लेकर कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। हाल ही में आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने उद्योग, ग्रामोद्योग, हथकरघा, कौशल विकास और श्रम विभाग की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ मैदानी स्तर पर सक्रियता दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाएं आम लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उद्योग विभाग ने जानकारी दी कि जिले में 79 लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संचालित हैं, जिनमें लगभग 60.59 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है और 761 लोगों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 14 प्रकरणों के लक्ष्य के विरुद्ध 132 लाख रुपये वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 80 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें 29 स्वीकृत हुए और 10 हितग्राहियों को ऋण का वितरण किया गया। श्रम विभाग की समीक्षा में पंजीकृत निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत जिले में 59 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। इन श्रमिकों को मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन, नोनी सशक्तीकरण, श्रमिक सियान सहायता तथा मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पात्र श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि 420 के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 120 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि 200 प्रशिक्षणरत हैं। जल वितरण संचालक, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल

इंस्टॉलेशन, असिस्टेंट मेसन, मशरूम उत्पादन और लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने शेष लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान अंत्योदय स्वरोजगार योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना तथा पीएम-अजय योजना के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाए ताकि युवाओं को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। बैठक के दौरान हथकरघा एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा अधूरी जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को योजनाओं की पूरी जानकारी रखने और हितग्राहियों तक उनका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में शिक्षा और कौशल विकास को जोड़ने की दिशा में भी जिले में नई पहल की गई। कलेक्टर के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा में वुडन आर्ट और बंबू आर्ट का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) सेवा केंद्र नया रायपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में जशपुर और सरगुजा के अनुभवी कारीगरों ने विद्यार्थियों को पारंपरिक हस्तशिल्प की बारीकियां सिखाईं। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने स्वयं लकड़ी और बांस से कलात्मक वस्तुएं बनाकर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। यह पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वहीं साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन, सुशासन तिहार और अन्य जनशिकायतों के मामलों में गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निपटारा नहीं, बल्कि ऐसा समाधान होना चाहिए जिससे आवेदक संतुष्ट हो। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, एग्रीस्टैग कार्य पूर्ण करने, गांवों में मुनादी कराने तथा बैकुंठपुर शहर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

बैठक के बाद उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर, रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, शिक्षा और सुशासन को लेकर जिला प्रशासन की सक्रियता से यह स्पष्ट है कि कोरिया जिले में शासन की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जिले में किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, बिना पुलिस को सूचना दिए मकान किराये पर देने पर कार्रवाई

बैकुण्ठपुर। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रोक्तिमा यादव ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार अब कोरिया जिले के नगरीय क्षेत्रों और नगर के बाहरी क्षेत्रों में मकान किराये पर देने से पहले किरायेदार का पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक कोरिया से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध करने की नीयत से आवासीय क्षेत्रों में छिपने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराना जरूरी है।

बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगा किराये पर मकान

आदेश के तहत कोई भी मकान मालिक किरायेदार का पूरा विवरण संबंधित थाना प्रभारी को दिए बिना मकान या उसका कोई हिस्सा किराये पर नहीं दे सकेगा। वैध पहचान पत्र के बिना किसी व्यक्ति को आवास किराये पर देना भी प्रतिबंधित रहेगा। मकान मालिकों को प्रत्येक किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा तथा यही जानकारी संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करानी होगी।

पहले से रह रहे किरायेदारों की जानकारी भी देनी होगी

आदेश जारी होने से पहले से किराये के मकान में रह रहे किरायेदारों के संबंध में भी मकान मालिकों को तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी देनी होगी। इसी तरह कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान भी पुलिस को जानकारी दिए बिना भवन किराये पर नहीं दे सकेगा और न ही ले सकेगा।

संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देना जरूरी

किरायेदार अथवा उनके यहां आने वाले किसी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

उल्लंघन पर धारा 223 के तहत कार्रवाई

कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश की जनसूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही इसकी प्रतियां संबंधित नगरीय निकायों, पुलिस थानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर चस्पा की जाएंगी।

रामानुजनगर थाने को मिला नया नेतृत्व, कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ी उम्मीद

*** थाना प्रभारी के रूप में विराट विसी ने संभाला कार्यभार, अपराध नियंत्रण और जनसहभागिता आधारित पुलिसिंग पर रहेगा विशेष फोकस**

रामानुजनगर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के बाद उप निरीक्षक विराट विसी ने रामानुजनगर थाना प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने के साथ ही क्षेत्रवासियों में बेहतर कानून व्यवस्था और प्रभावी पुलिसिंग को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।विराट विसी इससे पहले भी रामानुजनगर थाने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं, प्रेमनगर थाना प्रभारी के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय समस्याओं की उनकी समझ को देखते हुए लोगों को उनसे बेहतर कार्यशैली की अपेक्षा है।कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना, अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।क्षेत्र में चोरी, अवैध नशे के कारोबार और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लेकर लोगों में चिंता रही है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि नए थाना प्रभारी के नेतृत्व में नियमित गश्त, नशा विरोधी अभियान, बीट व्यवस्था को मजबूत करने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और लोगों का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा।

क्या कोरिया जिले में बेलगाम हो चुका है राजस्व तंत्र? अवैध प्लाटिंग, डायवर्सन और बिचौलियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न मामलों से जुड़े लोगों एवं स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जिले में अवैध प्लाटिंग, भूमि डायवर्सन, मुआवजा प्रकरणों और राजस्व न्यायालय की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना बाकी है।

सूत्रों के अनुसार, कमिश्नर कार्यालय द्वारा जिन क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई या आदेश जारी किए गए थे, उन्हीं क्षेत्रों की कुछ भूमि के डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि कुछ मामलों में नियमों की अनदेखी कर डायवर्सन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

सूत्रों का यह भी कहना है कि बैकुण्ठपुर की चर्चित भूमि से जुड़े मामले में, जहां सड़क मद में स्थित शीशम के पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने को लेकर पहले भी सवाल उठे थे, अब उसी भूमि के डायवर्सन की प्रक्रिया को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं संबंधित अधिकारियों का कहना है कि बैकुण्ठपुर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का कोई मामला नहीं है और लगाए जा रहे आरोप तथ्यात्मक नहीं हैं। राजस्व कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार झुमका वोट क्लब, रेलवे मुआवजा, राष्ट्रीय राजमार्ग मुआवजा तथा गेज नदी मुआवजा जैसे मामलों में बिचौलियों की सक्रियता की शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं। आरोप यह भी है कि राजस्व न्यायालय के अधिकांश प्रकरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ मुआवजा प्रकरणों का रिकॉर्ड अब तक ऑनलाइन नहीं होने से

पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। इसी बीच एक आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि उसने 30 जनवरी 2026 को संबंधित प्रकरण की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी उसे अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। आवेदक का आरोप है कि पूछताछ करने पर संबंधित कर्मचारी द्वारा अधिकारी की अनुमति नहीं होने की बात कही जाती है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि झुमका से जुड़े एक टेंडर प्रकरण में कथित रूप से रिश्वत की बातचीत होने की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस रिकॉर्डिंग की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी सक्षम जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। कार्यालय आने वाले कुछ लोगों का आरोप है कि आम आवेदकों को संबंधित लिपिक के पास बैठने या सीधे जानकारी लेने में कठिनाई होती है, जबकि कथित बिचौलियों की पहुंच आसान बताई जाती है। इसके अलावा मिशन स्कूल के पास स्थित भूमि, वन विभाग की भूमि तथा कथित अवैध प्लाटिंग से जुड़े अन्य मामलों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यदि इन आरोपों में तथ्य हैं तो यह गंभीर जांच का विषय हो सकता है। आवश्यक है कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और संबंधित सक्षम एजेंसियां पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं तथा सभी पक्षों को सुनते हुए तथ्यों को सार्वजनिक करें, ताकि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

नोटः यह समाचार आपके द्वारा साझा किए गए आरोपों और सूत्रों पर आधारित शैली में तैयार किया गया है। इसमें आरोपों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष तथा स्वतंत्र पुष्टि लंबित होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ताकि पत्रकारिता के संतुलन और कानूनी सावधानी का पालन हो।

कागजी फाइलों से डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ा सूरजपुर, ई-ऑफिस प्रशिक्षण से मिली नई दिशा

सूरजपुर, 04 अगस्त 2026 द शूटर। शासन के कामकाज को अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में जिला संयुक्त कार्यालय में मंगलवार को ई-ऑफिस प्रणाली पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुमित सिंह ने प्रतिभागियों को ई-फाइल निर्माण, नोटशीट तैयार करने, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन अनुमोदन और फाइल ट्रैकिंग की प्रक्रिया का व्यावहारिक अभ्यास कराया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बताया गया कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों में गति, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी तथा आमजन को सेवाएं अधिक समयबद्ध तरीके से मिल सकेंगी।

पंचायतीराज पदाधिकारियों ने समझा विकसित भारत जीरामजी का विजन एंव उद्देश्य

*** जिला पदाधिकारियों की रायपुर तथा जनपद पदाधिकारियों की सभागीय कार्यशाला संपन्न**

बैकुण्ठपुर। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबीजीरामजी योजना से पंचायती राज पदाधिकारियों अवगत कराने के लिए विस्तृत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके तहत जिला स्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए रायपुर में प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। साथ ही जनपद पंचायत स्तर के पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज पदाधिकारियों की सहभागिता से विकास के विजन को आगे ले जाना इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य रहा। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में भाग लेकर अब जिले के सभी पंचायती राज पदाधिकारी वीबी जीरामजी योजना से पूर्णतया अवगत होकर जिले के विकास में और तेजी से सहभागिता प्रदान कर सकेंगे।

प्रशिक्षण सह कार्यशाला का रोस्टर

राज्य कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सह कार्यशाला के रोस्टर अनुसार गत तीन अगस्त को पूरे राज्य के जिला पंचायत स्तरीय स्थायी समितियों के सभापतियों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें अध्यक्ष श्री मोहितराम पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े, श्रीमती स्नेहलता उदय, श्री सुरेश सिंह तथा श्रीमती शिवकुमारी तथा चार अगस्त को श्रीमती संगीता सोनवानी, श्री राजेश साहू, श्रीमती सुषमा कोराम, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह तथा श्रीमती गीता राजवाड़े को विकसित भारत जीरामजी योजना की विस्तृत जानकारी हेतु नामित किया गया। वहीं जनपद पंचायत के सभी पदाधिकारियों को चार अगस्त को संभागीय मुख्यालय में योजना से अवगत होने के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला में नामित किया गया।

निर्धारित प्रशिक्षण स्थल

जिला स्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों को विकसित भारत जीरामजी योजना की विस्तृत जानकारी हेतु ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं

ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा रायपुर में आहूत किया गया था। वहीं चार अगस्त को ही जनपद स्तरीय समस्त पंचायती राज पदाधिकारियों को संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में प्रशिक्षण सह कार्यशाला में योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के मूल विषय

विकसित भारत जीरामजी योजना के लिए राज्य स्तर तथा संभागीय स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पंचायती राज पदाधिकारियों को वीबीजीरामजी अधिनियम 2025 के विजन एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। साथ ही पंचायती राज पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं की जानकारी, योजना अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य, परिवारों का पंजीयन, ग्रामीण रोजगार, योजना के सभी प्रावधान, निगरानी और पर्यवेक्षण तथा शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के अभिसरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता से भी पंचायती राज पदाधिकारी अवगत हुए।

सहभागिता से विकास में आएगी गति

प्रशिक्षण सह कार्यशाला की जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्यकार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास ने बताया कि कलेक्टर कोरिया रोक्तिमा यादव के निर्देशन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्षेत्र के विकास के लिए वीबी जीरामजी अंतर्गत सतत कार्य किए जा रहे हैं। पंचायती राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण उपरांत उनकी सक्रिय सहभागिता से विकास कार्यों को और गति प्राप्त होगी।

जहाँ कभी हर गर्मी में सूख जाती थीं उम्मीदें, आज सालभर छलकता है जीवन... कालामांजल में जल संरक्षण ने लिखी बदलाव की नई कहानी

*** विकसित भारत जी-राम-जी योजना से बदली गाँव की तस्वीर, जल स्रोत बने जीवन और आजीविका का आधार, 250 से अधिक ग्रामीणों को मिला रोजगार**

सूरजपुर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। किसी भी गांव की असली समृद्धि उसकी मिट्टी और पानी से पहचानी जाती है। जब पानी साथ छोड़ देता है तो खेत सूने हो जाते हैं, मवेशी प्यासे रह जाते हैं और लोगों के चेहरों से उम्मीद की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। लेकिन सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत कालामांजल ने यह साबित कर दिया है कि यदि जल संरक्षण को जनभागीदारी का साथ मिल जाए, तो बदहाली की तस्वीर भी खुशहाली में बदल सकती है।

एक समय था जब कालामांजल में बारिश का अधिकांश पानी बिना रुके बह जाता था। गर्मी शुरू होते ही प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगते थे और ग्रामीणों के सामने पेयजल से लेकर खेती-किसानी तथा मवेशियों के लिए पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती थी। पानी की तलाश यहां के लोगों की रोजमर्रा की मजबूरी बन गई थी।

इसी चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास विकसित भारत जी-राम-जी योजना के माध्यम से किया गया। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले के निर्देशन में गांव में बड़े पैमाने पर कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम का निर्माण कराया गया। इन संरचनाओं ने वर्षा जल को रोककर धरती की प्यास बुझाई। साथ ही मिट्टी के कटाव पर प्रभावी नियंत्रण हुआ और जंगल से बहकर आने वाला कचरा भी डैम तक पहुंचने से पहले ही रुकने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि जल स्रोत पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और वर्षभर उपयोगी बन गया।

गांव के निवासी श्री मनोहर सिंह बताते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में पानी की एक-एक बूंद के लिए चिंता बनी रहती थी। मवेशियों को पानी पिलाना हो या खेतों का काम, हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वही जल स्रोत पूरे वर्ष ग्रामीणों की जरूरतें पूरी कर रहा है। आज इस पानी का उपयोग पेयजल, स्नान, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने और मत्स्य पालन जैसे कार्यों में किया जा रहा है। उनके अनुसार, पानी की स्थायी उपलब्धता ने ग्रामीणों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास पैदा किया है।

ग्राम सरपंच श्री अर्जुन सिंह बताते हैं कि इस योजना ने केवल जल संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि लगभग 250 से अधिक श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिली और गांव के विकास में लोगों की सहभागिता बढ़ी।

कालामांजल की यह कहानी केवल एक गांव में बने चेक डैम और कंटूर ट्रेंच की नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जिसने सूखी धरती को फिर से जीवन दिया। यहां रुका हुआ पानी केवल जल स्रोतों को नहीं भर रहा, बल्कि ग्रामीणों की उम्मीदों, आजीविका और भविष्य को भी सींच रहा है। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि जब योजनाएं ईमानदारी से धरातल पर उतरती हैं और लोग उसमें सहभागी बनते हैं, तब विकास केवल कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर घर और हर चेहरे पर साफ दिखाई देता है।

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिवरी में गूंजा हरियाली का संदेश, नन्हें हाथों ने रोपे भविष्य के सपनों के पौधे

*** एक विद्यार्थी, एक वृक्ष के संकल्प के साथ बच्चों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का प्रण, शिक्षकों ने बताया प्रकृति बचाने का महत्व**

रामानुजनगर, 04 अगस्त 2026, द शूटर।

धरती का भविष्य केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे संकल्पों से भी संवरता है। जब नन्हें हाथ मिट्टी में पौधा रोपते हैं, तो वे केवल एक पेड़ नहीं लगाते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और सुरक्षित पर्यावरण की नींव रखते हैं। इसी भाव को साकार करते हुए शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिवरी में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित परिसर निर्माण के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। पौधारोपण के साथ ही बच्चों ने इन पौधों की नियमित सिंचाई, देखभाल और संरक्षण का संकल्प भी लिया। विद्यालय परिसर बच्चों के उत्साह और हरियाली के संदेश से जीवंत दिखाई दिया।कार्यक्रम का मार्गदर्शन शिक्षक अम्बिका प्रसाद साहू ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण, घटते वन क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों से हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करने का आग्रह किया।इस अवसर पर शिक्षिका अनिता मिंज एवं शिक्षक मनोज उपाध्याय ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे केवल हरियाली नहीं बढ़ाते, बल्कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर सुरक्षा आवरण भी लगाया गया, ताकि पशुओं अथवा अन्य कारणों से उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। साथ ही विद्यार्थियों ने इन पौधों की नियमित निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं लेने का संकल्प लिया।कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने एक विद्यार्थी, एक वृक्ष का संदेश देते हुए सभी नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। हरित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण के सामूहिक संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय परिसर में रोपे गए ये पौधे आने वाले समय में केवल छाया ही नहीं देंगे, बल्कि बच्चों के भीतर प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की उस भावना को भी जीवित रखेंगे, जिसकी आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार : पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त की

अम्बिकापुर, 4 अगस्त 2026 द शूटर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

उक्ताशय पर मिली जानकारी अनुसार थाना गांधीनगर में दर्ज शिकायत के अनुसार, 2 अगस्त की देर रात ग्राम खलिबा निवासी सुरेन्द्र चेरवा ने एक महिला की नाबालिग बेटी को शादी का वादा कर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया। आरोप है कि उसने लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। परिवार को जानकारी मिलते ही उन्होंने लड़की को आरोपी के घर से वापस लाया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 497/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 65(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान लिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे अपने साथ ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत आरोपी की तलाश शुरू की। प्रयासों के बाद 20 वर्षीय सुरेन्द्र चेरवा, पिता सुखलाल चेरवा, निवासी ग्राम खलिबा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रशिक्षु उप निरीक्षक भारतीय मार्कण्डेय, सहायक उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर तथा आरक्षक कुंदन पाण्डेय, भीम सिंह, उमेश गुप्ता और दीपक सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कानून कोई नरमी नहीं बरतेगा।

किसानों को मिली राहत की नई उम्मीद, अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

*** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, कलेक्टर रेना जमील ने अधिक से अधिक किसानों से लाभ लेने की अपील**

सूरजपुर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। खेती केवल आजीविका नहीं, बल्कि किसान परिवारों की उम्मीदों, मेहनत और पूरे वर्ष के सपनों का आधार होती है। ऐसे में मौसम की एक मार या प्राकृतिक आपदा कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। इसी चिंता के बीच सूरजपुर जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2026 के लिए बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे वे किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे, जो किसी कारणवश पहले निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जो खेती-किसानी के कार्यों, लगातार बारिश, तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर सके थे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, कीट एवं रोगों सहित अन्य कृषि जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। समय सीमा बढ़ने से अब अधिक किसान अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित कर सकेंगे और किसी भी विपरीत परिस्थिति में आर्थिक नुकसान की भरपाई का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रहे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए 14 अगस्त 2026 से पहले अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी), संबंधित बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन अवश्य कराएं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अंतिम दिनों की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए किसान समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें तथा आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

कलेक्टर ने उप संचालक कृषि एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी हर गांव तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम पंचायतों में मुनादी, कृषक चौपाल तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि जिले का कोई भी किसान जानकारी के अभाव में इस योजना से वंचित न रह जाए। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि बदलते मौसम और अनिश्चित जलवायु के दौर में फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक बीमा नहीं कराया है, उनके लिए यह बढ़ी हुई समय-सीमा एक सुनहरा अवसर है। समय पर किया गया यह छोटा सा कदम भविष्य में आने वाले बड़े आर्थिक संकट से बचाने का सहारा बन सकता है।

तीर-धनुष छोड़ जंगल के राजा की हिफाजत का लिया संकल्प, पण्डो जनजाति ने वन विभाग को सौंपे शिकार के उपकरण

बाघ चौपाल में गूंजा संरक्षण का संदेश, रेंजर विकास गुप्ता बोले, वन्यजीव दिखें तो तुरंत विभाग को दें सूचना

ओड़गी, 04 अगस्त 2026, द शूटर।जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि अनगिनत जीवों का साझा घर है। जब इस घर के सबसे ताकतवर प्रहरी बाघ की सुरक्षा का संकल्प स्वयं ग्रामीण लेने लगें, तो यह बदलाव केवल एक अभियान नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति जागी नई चेतना का संकेत बन जाता है। सूरजपुर वनमण्डल के कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र में आयोजित बाघ चौपाल इसी सकारात्मक बदलाव का साक्षी बनी, जहां विशेष रूप से पण्डो जनजाति के ग्रामीणों ने शिकार में उपयोग होने वाले तीर-धनुष, फंदे, तार और जाल स्वेच्छा से वन विभाग को समर्पित कर वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा धरसेड़ी वन बीट के बिरसा पारा, आनंदपुर वन बीट के आमापानी पारा, भवंरखोह वन बीट के सेमरखांड पारा तथा गेरुहाड़ाड पारा में आयोजित बाघ चौपाल में ग्रामीणों को बाघों के प्राकृतिक व्यवहार, जंगल के पारिस्थितिक संतुलन में उनकी भूमिका और जैव विविधता संरक्षण के महत्व की विस्तार से जानकारी दी गई।इस दौरान कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी विकास गुप्ता ने कहा कि बाघ और अन्य वन्यजीव जंगल की अमूल्य धरोहर हैं। यदि किसी क्षेत्र में बाघ अथवा किसी अन्य वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी परिस्थिति में वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें। चौपाल में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियां, मवेशियों की सुरक्षा, वन अपराधों की रोकथाम तथा जनसहभागिता के महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों को समझाया गया कि जंगल और वन्यजीव सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी प्राकृतिक धरोहर का लाभ उठा सकेंगी।वन विभाग की अपील का सकारात्मक असर भी देखने को मिला। कई ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने पास रखे तीर-धनुष, फंदे, तार, जाल एवं अन्य शिकार सामग्री वन विभाग को सौंपते हुए भविष्य में वन एवं वन्यजीव संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में परिक्षेत्र अधिकारी विकास गुप्ता, परिक्षेत्र सहायक सुदामा सिंह, रामनाथ सिंह, टाइगर ट्रेकर्स दल के सदस्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बाघ चौपाल ने यह संदेश दिया कि जब जंगल के आसपास रहने वाले लोग ही संरक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, तब वन्यजीवों की सुरक्षा का अभियान वास्तव में जनआंदोलन का रूप ले लेता है।

सरगुजा संभाग में प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी घोषित

*** नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन को मिलेगी नई दिशा, कर्मचारी हितों की आवाज को और मजबूती देने का संकल्प**

अम्बिकापुर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। किसी भी कर्मचारी संगठन की असली ताकत उसके पद नहीं, बल्कि उसके सदस्यों का विश्वास और उनकी अपेक्षाएं होती हैं। इन्हीं अपेक्षाओं को नई ऊर्जा और नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने सरगुजा संभाग की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। संगठन को उम्मीद है कि नवगठित टीम कर्मचारियों के अधिकारों, समस्याओं और हितों की लड़ाई को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए संगठनात्मक एकजुटता को नई मजबूती प्रदान करेगी।रायपुर के टाउन हॉल में 02 अगस्त 2026 को आयोजित प्रांतीय आम सभा में प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने संघ के संविधान में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सरगुजा संभागीय कार्यकारिणी की घोषणा की। यह गठन प्रदेश महामंत्री (सरगुजा) आनंद यादव की अनुशंसा के बाद किया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही संघ ने नई कार्यकारिणी की अधिसूचना भी जारी कर दी है।नई संभागीय कार्यकारिणी में दिनेश कुमार कश्यप को

संभागीय अध्यक्ष, राजेश्वर सिंह को कार्यकारी संभागीय अध्यक्ष, सुधीर कुमार राणा एवं राहुल कुमार यादव को संभागीय उपाध्यक्ष, चन्द्रदेव चक्रधारी को संभागीय सचिव, रामजनम यादव को संभागीय कोषाध्यक्ष तथा योगेश कुमार को संभागीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बुजेश बिसेन को स्वास्थ्य विभाग, सरगुजा संभाग का विभागीय अध्यक्ष तथा विक्रम मिरी को आदिवासी जाति कल्याण विभाग, सरगुजा संभाग का विभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।संघ का मानना है कि नई कार्यकारिणी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को शासन-प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने के साथ-साथ संगठन को जमीनी स्तर तक और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने का कार्य करेगी। कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, संगठनात्मक विस्तार, आपसी समन्वय और सकारात्मक संवाद को नई टीम अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेगी।प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा और प्रदेश महामंत्री आनंद यादव ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन तभी मजबूत होता है, जब उसके पदाधिकारी कर्मचारियों के सुख-दुख में सहभागी बनकर उनकी आवाज को मजबूती से उठाएं। नई कार्यकारिणी से यही अपेक्षा है कि वह कर्मचारियों के विश्वास पर खरी उतरते हुए सरगुजा संभाग में संगठन को नई पहचान और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी।

स्टारमर का इस्तीफा: ब्रेक्ज़िट की गलतियों का साया ब्रिटेन पर

स्टारमर का इस्तीफा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का इस्तीफा उस असाधारण राजनीतिक अस्थिरता का एक और अध्याय है जिसने पिछले दशक में ब्रिटेन को अपनी चपेट में ले रखा है। ब्रिटेन में शायद ही कोई उनके जाने से सचमुच हैरान हुआ हो। उन्हें एक ऐसा देश मिला जो 2016 के ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह से पैदा हुए बंटवारे के कारण गहरे घावों से जूझ रहा था; उस जनमत संग्रह के वोटों की गिनती ठीक दस साल पहले इसी हफ़्ते शुरू हुई थी। तब से, देश किसी मकसद या एकजुटता को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्थिक ठहराव, बढ़ती बेरोजगारी, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और लोकलुभावन राजनीति के उभार ने किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। विधायी ढांचा और संवैधानिक जनादेश में टकराव फिर भी, स्टारमर के आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उन्होंने तब समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई जब सख्ती की जरूरत थी और वे ऐसी कल्पनाशील नीतियां बनाने में नाकाम रहे जो लेबर पार्टी में जनता का भरोसा फिर से कायम कर सकें। स्थानीय निकाय चुनावों में लेबर पार्टी को मिली करारी हार के बाद उनके पास राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की बहुत कम गुंजाइश बची थी। उनके इस्तीफे के साथ ही वे पिछले 10 सालों में पद छोड़ने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो यह दिखाता है कि ब्रिटिश राजनीति कितनी उथल-पुथल भरी हो गई है। लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा अब स्टारमर के उत्तराधिकारी के तौर पर एंडी बर्नहम का आना तय लग रहा है; उपचुनाव में जीत के बाद लेबर पार्टी के दूसरे दावेदार भी ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि, आगे का रास्ता आसान नहीं है। बर्नहम को भी लगभग वही समस्याएं विरासत में मिलेंगी जिन्होंने उनके पूर्ववर्ती को परेशान किया था। ब्रिटेन की सार्वजनिक सेवाओं के लिए लगातार फंड की कमी बनी हुई है, और उन्हें फिर से पटरी पर लाने के लिए ऐसे संसाधनों की जरूरत होगी जिन्हें जुटाना ट्रेजरी के लिए मुश्किल है। साथ ही, रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोर इस बात पर है कि यूरोपीय देशों को अब यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका हमेशा उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उठाता रहेगा। सेना के किसी भी बड़े विस्तार के लिए जरूरी होगा कि दूसरी जगहों पर मुश्किल कटौती की जाए, जबकि नागरिक अभी भी एक उदार कल्याणकारी राज्य से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा, व्हाइट हाउस में ट्रंप के बचे हुए कार्यकाल के दौरान वॉशिंगटन के साथ संबंध संभालने का मुश्किल काम भी है। स्टारमर के फैसले पर तब सवाल उठे थे जब उन्होंने वॉशिंगटन में एक विवादित राजदूत नियुक्त किया था, जिनके एपस्टीन मामले से कथित संबंध बाद में राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बने, भले ही प्रधानमंत्री को खुद इसके बारे में पता न हो। : विस्तार से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई ब्रिटेन के अधूरे ब्रेक्ज़िट सवाल इसके बावजूद, ब्रिटेन की पार्टी-केंद्रित संसदीय प्रणाली शीर्ष स्तर पर बार-बार होने वाले बदलावों के बीच भी एक हद तक निरंतरता बनाए रखती है। सरकारें सिर्फ.इसलिए नहीं गिरतीं कि कोई एक नेता चला गया, क्योंकि एक व्यक्ति की जगह तुरंत दूसरा ले लेता है। फिर भी, जिस आसानी से प्रधानमंत्री बदले जा सकते हैं, उससे एक ज्यादा चिंताजनक सच्चाई ओझल नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन अब भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है जो ब्रेक्ज़िट के समय से ही बने हुए हैं। विकास को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए, सरकारी संस्थाओं में भरोसा कैसे बहाल किया जाए, और सुरक्षा, समृद्धि व सामाजिक न्याय से जुड़ी अलग-अलग उम्मीदों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए? हो सकता है कि एंडी बरनहम जल्द ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच जाएं

नियम तोड़ने का लाइसेंस, जो असल में जान लेने का लाइसेंस साबित हुआ

नियम तोड़ने का लाइसेंस लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग इंस्टिट्यूट में लगी भीषण आग, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलअंदाजी का नतीजा थी। वह इमारत रहने के लिए बनी थी। फिर भी, नगर निगम के नियमों को खुलेआम तोड़कर उसे कमर्शियल जगह में बदल दिया गया और सालों तक चलाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकारियों का ध्यान पहले ही इस इमारत पर जा चुका था। 2016 में, डेवलपमेंट अथॉरिटी के सक्षम अधिकारी ने मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। हैरानी की बात है कि दो महीने से भी कम समय में वह आदेश वापस ले लिया गया। इतने बड़े बदलाव से परेशान करने वाले सवाल उठते हैं। किन हालात में गिराने का आदेश रद्द किया गया? इमारत को बचाने के लिए किसने दबाव डाला? इस फैसले से किसे फायदा हुआ? यह सोचना भी मुश्किल है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निकायों, बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारियों की जानकारी और मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी कमर्शियल इमारत बन सकती थी और चल सकती थी। इस त्रासदी के लिए जवाब चाहिए, खोखली बातें नहीं। लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा नियम तोड़ने का देशव्यापी पैटर्न हालांकि, लखनऊ की इस घटना को सिर्फ. उत्तर प्रदेश की समस्या मानना गलत होगा। यह समस्या पूरे देश में है। खुद राजधानी में, सिर्फ.पाँच कमरों वाले गेस्ट हाउस को गैर-कानूनी तरीके से बढ़ाकर उसमें लगभग दो दर्जन बेड लगा दिए गए थे। जब वहाँ आग लगी, तो कई लोग फँस गए क्योंकि आने-जाने के लिए एक ही संकरा रास्ता था। भारत के शहरों में ऐसी कहानियाँ दोहराई जाती रहती हैं। मंजूर किए गए प्लान से ज्यादा बड़ी इमारतें बन जाती हैं, बेसमेंट को कमर्शियल जगहों में बदल दिया जाता है, अतिरिक्त मंज़िलें जोड़ दी जाती हैं, और कम बिजली की खपत के हिसाब से बने बिजली सिस्टम पर कई एयर-कंडीशनर और भारी उपकरण चलाए जाते हैं। ओवरलोड वायरिंग खराब हो जाती है, चिंगारियाँ निकलती हैं और आग लग जाती है। फिर भी, जाँच-पड़ताल सिर्फ.दिखावे के लिए होती है, गलत तरीकों से नियमों का उल्लंघन ठीक कर दिया जाता है, और नियम तोड़ने वाले फलते-फूलते रहते हैं। इस खतरनाक सिस्टम की जड़ में भ्रष्टाचार है, जहाँ नियमों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, फाइलें गायब हो जाती हैं, और निजी फायदे के लिए लोगों की सुरक्षा की बलि दे दी जाती है। सार्थक जवाबदेही की जरूरत करना और सात दिनों में रिपोर्ट देने के लिए दो सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना स्वागत योग्य शुरूआती कदम हैं, लेकिन ये सिर्फ. लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए दिखावटी कार्रवाई नहीं बननी चाहिए। जवाबदेही सिर्फ.बिल्डिंग के मालिकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें वे सभी अधिकारी भी शामिल होने चाहिए

शुरूआत: विधायी ढांचा और संवैधानिक जनादेश में टकराव

संवैधानिक जनादेश में टकराव दो रिसर्च पेपर—श्रीवास्तव का 'गुजरात में शहरीकरण वाले इलाकों पर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991 के सामाजिक-स्थानिक परिणाम' और तेजानी का 'गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट: बहिष्कार का भगवा भूगोल' (दोनों 2002 में आए, जो हर लिहाज से सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत मुश्किल साल था)—और संविधान के संदर्भ में इस एक्ट का विश्लेषण, उन लोगों के लिए एक साफ चेतावनी है जो बातों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों रिसर्च पेपर दिखाते हैं कि शहरी भारत का स्थानिक ढांचा अब सिर्फ. अर्थशास्त्र या जनसंख्या की कहानी नहीं रह गया है। यह धीरे-धीरे लेकिन तेजी से कानून की कहानी बन गया है: कि कैसे कानूनी ढांचे का इस्तेमाल समुदायों के बीच अदृश्य दीवारें खड़ी करने के लिए किया जा सकता है—ऐसी दीवारें जो उस हिंसा या अव्यवस्था के खत्म होने के बाद भी बनी रहती हैं, जिनके नाम पर उन्हें जायज ठहराया गया था। गुजरात डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट की तर्ज. पर बने रेगुलेटरी सिस्टम का फैलना—ऐसे कानून जो अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच प्रॉपर्टी के लेन-देन को प्रशासनिक जांच और मंजूरी के दायरे में लाते हैं—समकालीन भारत में कानून और सांप्रदायिक भूगोल के सबसे अहम, लेकिन सबसे कम जांचे-परखे मेल में से एक है। विद्वानों ने इस घटना को ₹एथ्नोक्रेटिक अर्बन प्लानिंग₹ (जातीय-धार्मिक आधार पर शहरी योजना) कहना शुरू कर दिया है: यानी ऊपर से निष्पक्ष और व्यवस्था बनाए रखने वाले कानून का इस्तेमाल धार्मिक अलगाव को शहर के परिदृश्य की एक स्थायी विशेषता के तौर पर संस्थागत बनाने के लिए करना। इस परिभाषा के लिए संविधान के नजरिए से कड़ी जांच-पड़ताल की जरूरत है। क्या यह संवैधानिक रूप से गारंटीकृत नागरिक अधिकारों में विधायी दखल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप रिहायशी आवाजाही कम होने से गलत तरीके से पाबंदी लगती है? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इन कानूनों का ₹काम करने का तरीका₹ ऊपर से देखने में मामूली लगता है। वे अपने टेक्स्ट में किसी भी लेन-देन पर रोक नहीं लगाते हैं। वे बस यह चाहते हैं कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच बिक्री या ट्रांसफर से पहले कलेक्टर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि लेन-देन से सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी या जनसंख्या का ध्रुवीकरण नहीं बढ़ेगा। निगरानी की भाषा सार्वजनिक प्रशासन के आपातकालीन टूलकिट से ली गई है, जिसे जानबूझकर इतना व्यापक रखा गया है कि इसमें लगभग हर ऐसी स्थिति शामिल हो सके जिसे सरकार असुविधाजनक मान सकती है। ब्रिटेन पर जब निगरानी गेटकीपिंग बन जाती है: अनुच्छेद 19(1)(ी) और रहने का अधिकार फिर भी, जो निगरानी जैसा दिखता है, वह असल में बिना कहे गेटकीपिंग (आवाजाही पर नियंत्रण) है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ी) के तहत देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार राज्य की कृपा से मिलने वाली कोई सुविधा नहीं है: यह एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर रोक लगाने के लिए कानूनी वैधता और आनुपातिकता दोनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 रउउ 248 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाते हुए यह तय किया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने वाला कोई भी कानून या प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी कार्यकारी शक्ति को छिपाने वाली महज एक औपचारिकता; यह एक ऐसा मानक है जिसे ये कानून पूरा करने में संघर्ष करते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (1985) 3 रउउ 545 मामले में कोर्ट की इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, संवैधानिक मांग स्पष्ट हो जाती है: किसी व्यक्ति की रहने की जगह चुनने की पसंद, और उस पसंद को पूरा करने के लिए वह किसके साथ लेन-देन कर सकता है, इसे ऐसी नौकरशाही मंजूरी पर निर्भर नहीं किया जा सकता जिसके मानक अनिश्चित हों, जिसका इस्तेमाल व्यावहारिक और वास्तविक अर्थों में किसी समीक्षा के दायरे में न आता हो, और जिसके नतीजे स्पष्ट रूप से धार्मिक पहचान से जुड़े हों। अ'२ङ्ग र्फी - राजनीतिक चुनौती के बीच ठाकरे गुट का फोकस: विस्तार से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई अनुभवजन्य रिकॉर्ड उस बात की पुष्टि करता है जिसकी भविष्यवाणी सैद्धांतिक विश्लेषण करता है। ये नियामक ढांचे पड़ोस की खुली प्रकृति को खत्म कर देते हैं, जिससे अलग-अलग धर्मों के लोगों के साथ मिलकर रहने वाली जगहों का स्वाभाविक विकास रुक जाता है। जो चीज खुद को अलग-थलग करने से शुरू हो सकती है—अक्सर आस-पास हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बचने की कोशिश के तौर पर, जो अस्थायी और मजबूरी में किया गया कदम होता है

राजनीतिक चुनौती के बीच ठाकरे गुट का फोकस: विस्तार से ज्यादा अस्तित्व की लड़ाइ

ठाकरे परिवार के लिए अब प्राथमिकता पार्टी का पुनरुद्धार नहीं, बल्कि उसका अस्तित्व बचाना बन गया है पिछले हफ़्ते महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं जिनकी उम्मीद तो थी, लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए ये चौंकाने वाली थीं—खासकर मुंबई के प्रमुख राजनीतिक परिवार, ठाकरे परिवार के लिए। क्षेत्रीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, शिवसेना (वइळ) गुट के लोकसभा के छह सदस्य अचानक कई दिनों तक 'संपर्क से बाहर' हो गए। इस बात को लेकर अटकलें तेज थीं कि आखिर क्या हो रहा है, और फिर अचानक खबर आई कि उन्होंने शिवसेना (वइळ) छोड़ दी है और महाराष्ट्र के डिप्टी उट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विरोधी शिवसेना गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना (वइळ) के जाने-माने प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पहले तो यह समझ नहीं पाए कि सांसद क्या करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में मीडिया से बातचीत में वे उनके खिलाफ तेजी से आक्रामक हो गए और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से उन्हें अपशब्द भी कहे। इस हफ़्ते की शुरूआत तक यह साफ हो गया था कि छह सांसदों ने शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला कर लिया है और संसद के आगामी मॉनसून सत्र में वे सत्ताधारी पार्टी के साथ बैठेंगे। अपने 60 साल के इतिहास में शिवसेना (वइळ) कभी भी इतनी कमजोर और असुरक्षित नहीं दिखी जितनी अब दिख रही है। इससे कई सवाल उठते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य आने वाले महीनों या सालों में राज्य विधानसभा और बृहन्मुंबई नगर निगम (इटउ) में अपने लोगों को कैसे एकजुट रखेंगे। भावनाओं पर बनी पार्टी पारंपरिक रूप से, शिवसेना हमेशा से ऐसी पार्टी रही है जो किसी भी अन्य कारक की तुलना में भावनाओं के आधार पर ज्यादा चलती है। भावनात्मक भाषण, पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में भावनात्मक संपादकीय और पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की भावनात्मक अपीलों ने करोड़ों शिवसैनिकों को प्रेरित किया, और उन्होंने चुनावों से पहले पूरे दिल-ओ-जान से प्रचार अभियान में काम किया। शिवसेना में धोखाधड़ी को हमेशा सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। पार्टी का कोई भी सदस्य अगर पार्टी छोड़कर किसी दूसरे राजनीतिक संगठन में शामिल होता था, तो उसे गद्दार माना जाता था। हालाँकि, पिछले कुछ दिनों में इस तथाकथित धोखे से जुड़ा कलंक खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले चार सालों में यह दूसरी बार है जब चुने हुए प्रतिनिधियों ने अचानक दो-तिहाई बहुमत के साथ एक गुट बनाया है और विरोधी खेमे में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे ने पहली बार जून 2022 में ऐसा किया था, जब वे शिवसेना के 40 विधायकों को साथ ले गए थे, और अब उन्होंने वइळ गुट के छह और सांसदों के साथ ऐसा किया है। कई लोगों का कहना है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में मिली सफलता ने शिंदे, उनकी पार्टी और वइळ गुट से अलग हुए छह नेताओं में यह भरोसा जगाया है कि वे लंबे समय में जनता के किसी विरोध का सामना किए बिना ऐसा फिर से कर सकते हैं। शिंदे और मजबूत हुए छह सांसदों के इस कदम से महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है। कांग्रेस, ठउढ (रढ) और शिवसेना (वइळ) वाले विपक्षी गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' (टश्अ) को इस बगावत से बड़ा झटका लगा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में टश्अ ने 48 में से 31 सीटें जीती थीं, जिससे संकेत मिलता था कि लोकसभा में विपक्ष की वापसी संभव है। अब इन 31 सांसदों में से छह इखढ के नेतृत्व वाले ठऊअ में शामिल हो गए हैं, जिससे पलड़ा कुछ हद तक इखढ के पक्ष में झुक गया है। इससे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काफी ताकत मिलेगी क्योंकि अब लोकसभा में उनके 13 सदस्य और राज्य विधानसभा में उनके अपने 57 सदस्य हैं, जिससे वे स्पष्ट रूप से इखढ के बाद महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गए हैं। असल में, शिंदे के लोकसभा सांसदों की संख्या अब महाराष्ट्र में इखढ द्वारा जीती गई सीटों की संख्या से भी ज्यादा है। पिछले हफ्ते हुई घटनाओं से जो मुख्य बात सामने आई है, वह है एकनाथ शिंदे का और मजबूत होना। अब चर्चा इस बात की है कि शिंदे की पार्टी को केंद्र सरकार में कैबिनेट में एक और पद मिल सकता है। ठाकरे परिवार के लिए अनिश्चितता दूसरी मुख्य बात निश्चित रूप से ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से ठाकरे परिवार कमजोर हुआ है, और यह शायद इस साल उनके लिए दूसरा बड़ा झटका है; इससे पहले वे इस साल की शुरूआत में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ सीट-शेयरिंग गठबंधन करने के बावजूद इटउ चुनाव नहीं जीत पाए थे। हालात को और खराब करने वाली बात यह चर्चा है कि शिवसेना (वइळ) के विधायकों में भी इसी तरह की फूट देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी शिवसेना (वइळ) के 20 विधायक हैं और ऐसी अटकलें हैं कि उनमें से कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पिछले हफ़्ते छह सांसदों ने पार्टी छोड़ी थी। एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने दावा किया कि पिछले हफ़्ते महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वह ₹सिर्फ. एक फिल्म का ट्रेलर₹ था। अगर आने वाले हफ़्तों या महीनों में दो-तिहाई विधायक शिवसेना (वइळ) छोड़ने का फैसला करते हैं,

अल नीनो से खरीफ की फसल कम हो सकती है, लेकिन इससे खाद्य सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा

नीनो से खरीफ की फसल कम देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का मौसम (जून से सितंबर) शुरू हो चुका है, लेकिन खेती-बाड़ी को लेकर मॉनसून की धीमी रफ़्तार, अल-नीनो का खतरा और सिंथेटिक फर्टिलाइजर की कमी जैसी चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि 4 जून को केरल के तट पर मॉनसून ने दस्तक दी, लेकिन अगले 10 दिनों में उत्तर की ओर इसकी रफ़्तार थम गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश के अपने अनुमान को पहले के 92% से घटाकर 90% (870` के लंबे समय के औसत का) कर दिया है, जिसमें +/- 4% की मॉडल त्रुटि की गुंजाइश है। 870` का 90% लगभग 780` होता है। अ'२ङ्ग र्फी - शुरूआत: विधायी ढांचा और संवैधानिक जनादेश में टकराव 'सुपर अल-नीनो', गंभीर सूखा और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा जैसे शब्द चर्चा में हैं। तो, स्थिति कितनी गंभीर है? अल-नीनो का खतरा बहुत वास्तविक है, लेकिन हमें अभी यह नहीं पता कि यह कितना गंभीर होगा। फिर भी, हमें सबसे खराब स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। बारिश का बंटवारा ज्यादा अहम सबसे पहले, यह समझना जरूरी है कि मौसम के आखिर में दर्ज की गई कुल बारिश की मात्रा से कहीं ज्यादा अहम बारिश का समय (चार महीनों के दौरान) और जगह (भौगोलिक) के हिसाब से बंटवारा है। इसलिए, अगर बारिश की मात्रा कम भी हो—मान लीजिए 800`—लेकिन वह समय और जगह के हिसाब से सही ढंग से बंटी हो, तो फसल के संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है। हम प्रकृति की दया पर निर्भर हैं। देश भर के बड़े जलाशयों में पानी का भंडारण मुश्किल से संतोषजनक है। इसके अलावा, पिछले छह से आठ हफ़्तों में, खासकर देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में, लू (हीटवेव) की स्थिति के कारण मिट्टी की नमी कम हो गई है। जोखिम प्रबंधन का एक अच्छा सिद्धांत यह है कि संभावित स्थितियों का अनुमान लगाया जाए और बुरे नतीजों को कम करने के लिए रणनीतियां बनाई जाएं। इसके लिए ज़िलेवार आकस्मिक योजना एक अच्छी शुरूआत हो सकती है। मौसम की एक घटना के तौर पर, अल-नीनो का संबंध आमतौर पर कम बारिश, सूखे हालात और मॉनसून के असामान्य व्यवहार से होता है। इसके कारण मॉनसून जल्दी या देर से आ सकता है, बारिश जल्दी या देर से जा सकती है, लंबे समय तक बारिश नहीं हो सकती है या बिना बारिश के बहुत सारे बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के ऐसे पैटर्न फसल को उलझन में डालते हैं और विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, बिना बारिश के लंबे समय तक बादल छाए रहने से अक्सर कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है और फसलें कीड़ों के हमले की चपेट में आ जाती हैं।

वीटो से आगे: दुनिया को शांति के लिए एक नए ढांचे की जरूरत क्यों है?

दुनिया को शांति के लिए एक नए ढांचे की जरूरत क्यों है? चित्तरवु रघु द्वारा 21वीं सदी में हो रहे युद्ध एक असहज सच को सामने ला रहे हैं: सैन्य श्रेष्ठता अब राजनीतिक जीत की गारंटी नहीं देती। यह सोच कि जबरदस्त तकनीकी क्षमता, आर्थिक ताकत और आधुनिक हथियार निर्णायक नतीजे दिला सकते हैं, धीरे-धीरे एक अधिक गंभीर वास्तविकता में बदल रही है। आपस में जुड़े हुए इस दौर में, संघर्ष लंबे, महंगे और बिना किसी ठोस नतीजे वाले हो गए हैं; ये अपने पीछे तबाही तो छोड़ते हैं, लेकिन शायद ही कभी कोई स्पष्ट विजेता सामने आता है। हाल के भू-राजनीतिक संकटों ने इस बदलाव को उजागर किया है। चाहे वह रूस-यूक्रेन का लंबा संघर्ष हो या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, सैन्य शक्ति की सीमाएं स्पष्ट होती जा रही हैं। उन्नत क्षमताओं वाले देश भी जवाबी कार्रवाई, आर्थिक व्यवधान और राजनयिक गतिरोध के चक्र में फंस गए हैं। अंततः बातचीत की मेज पर लौटने से एक ऐसा सबक मिला है जिसे इतिहास बार-बार सिखाने पर आमादा दिखता है: आधुनिक युद्ध से मिलने वाले फायदे कम होते जा रहे हैं, और केवल बल प्रयोग से स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती। बार-बार होने वाले युद्ध संघर्ष की बदलती प्रकृति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर युद्ध अब निर्णायक समाधान देने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के पास उन्हें रोकने और सुलझाने के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद हैं? दुर्भाग्य से, इसका जवाब बेहद चिंताजनक है। संयुक्त राष्ट्र का गठन दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद एक महत्वाकांक्षी सोच के साथ हुआ था। यह मानवता के उस संकल्प का प्रतीक था जिसके तहत ऐसी संस्थाएं बनाई जानी थीं जो किसी और वैश्विक तबाही को रोक सकें। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मजबूत किया गया, समझौते किए गए और सुरक्षा परिषद को शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर भी, दशकों के समझौतों, प्रस्तावों और राजनयिक पहलों के बावजूद, दुनिया लगातार युद्धों और मानवीय संकटों को देख रही है। और भी चिंता की बात यह है कि इनमें से कई संघर्ष इसलिए जारी हैं क्योंकि समाधान उपलब्ध नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि शांति लागू करने वाले तंत्र खुद ही सीमित हैं। इस संरचनात्मक कमजोरी की जड़ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पावर है। 1945 में युद्ध के बाद की दुनिया की वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई यह व्यवस्था शायद शीत युद्ध के शुरूआती दशकों में स्थिरता लाने में मददगार रही हो। हालांकि, 21वीं सदी का भू-राजनीतिक परिदृश्य उस दौर से बहुत अलग है। जिसे संतुलन बनाए रखने के एक साधन के तौर पर बनाया गया था, वह धीरे-धीरे गतिरोध पैदा करने वाला साधन बन गया है। ब्रिटेन पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बार-बार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वे किसी न किसी स्थायी सदस्य के रणनीतिक हितों के खिलाफ थे। नतीजतन, अंतरराष्ट्रीय कानून अक्सर सार्वभौमिक होने के बजाय चुनिंदा (शीˆ्र५ी) लगता है। छोटे देश वैश्विक नियमों के अनुशासन के दायरे में रहते हैं, जबकि बड़ी ताकतें और उनके सहयोगी अक्सर असल जवाबदेही से बच निकलते हैं। नतीजा यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को समान नियमों वाली प्रणाली के बजाय भू-राजनीतिक विशेषाधिकारों से बनी एक पदानुक्रमित व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। 1945 के लिए बनाए गए ढांचे, डिजिटल परस्पर निर्भरता, बहुध्रुवीयता और साझा चुनौतियों से बदली हुई दुनिया को हमेशा के लिए नहीं चला सकते। साथ ही, दुनिया में भी गहरे बदलाव आए हैं। वैश्वीकरण ने देशों को आर्थिक परस्पर निर्भरता के ऐसे नेटवर्क में पिरो दिया है, जैसा मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। सप्लाई चेन महाद्वीपों तक फैली हुई हैं। वित्तीय बाजार सीमाओं के पार काम करते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियां ऐसी साझा चिंताएं बन गई हैं जिनका समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास हाल ही में हुई उथल-पुथल ने इस सच्चाई को साफ तौर पर दिखाया है। एक संकरे समुद्री रास्ते में हुई घटनाओं का असर एनर्जी मार्केट पर पड़ा और इसने उस इलाके से बहुत दूर की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। दूसरी जगहों पर हुए संघर्षों के दौरान भी ऐसे ही पैटर्न देखे गए हैं। युद्ध के नतीजे अब सिर्फ. युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहते; वे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। हैरानी की बात है कि यह आपसी जुड़ाव इंसानियत के लिए सबसे बड़ा मौका भी हो सकता है। आपसी निर्भरता ने ऐसे प्रभाव डालने के तरीके पैदा किए हैं जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय मौजूद नहीं थे। कोई भी देश, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर देश भी, खुद को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम और कूटनीतिक रिश्तों से पूरी तरह अलग नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया में जहाँ अलग-थलग रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, सामूहिक कार्रवाई में पहले से कहीं ज्यादा क्षमता है। इस सच्चाई से ग्लोबल गवर्नेंस के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसे सुधारों पर चर्चा शुरू करनी चाहिए जो दबदबे (ॊीङ्गल्ल८) से ऊपर जवाबदेही को रखें। संयुक्त राष्ट्र को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके संस्थागत ढांचे में तुरंत बदलाव की जरूरत है।

निर्मल पुर्जा समेत 10 पर्वतारोहियों की मौत, जानिए 'निम्स दाई' ने कैसे रचा था इतिहास

दुनिया के मशहूर पर्वतारोही निर्मल 'निम्स दाई' पुर्जा की ब्रॉड पीक पर हुए हिमस्खलन में मौत हो गई है. उनकी संस्था इलीट एक्सपेड ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है.बीबीसी नेपाली के अनुसार, इस हादसे में अभियान दल के सभी 10 सदस्यों की जान चली गई है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पर्वतारोहियों के निधन पर दुख जताया है.बीबीसी नेपाली से बात करते हुए सेवन समिट्स ट्रेक्स के अध्यक्ष मिंगमा शेरपा ने कहा कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि कोई भी जीवित नहीं बचा है.इलीट एक्सपेड के मुताबिक, निर्मल पुर्जा के साथ उनके भरोसेमंद क्लाईबिंग पार्टनर और गाइड पुर बहादुर गुरुंग (युक्टा) और निमा शेरपा की भी इस त्रासदी में मौत हो गई. इलीट एक्सपेड ने इंस्टाग्राम पर लिखा, पर्वतारोहण जगत ने एक महान पर्वतारोही और ऐसे लीडर को खो दिया है, जिन्होंने अपने साहस, विनम्रता और दृढ़ विश्वास से लाखों लोगों को प्रेरित किया. निर्मल पुर्जा ने अपनी उपलब्धियों के जरिए दुनिया को दिखाया कि बड़े सपने देखने और सीमाओं को चुनौती देने से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. इससे पहले गिलगित-बल्तिस्तान पुलिस ने शुक्रवार को फेसबुक पर एक बयान में बताया था कि ब्रॉड पीक से अब तक चार शव बरामद हुए हैं.इनमें से दो की पहचान पर्वतारोही संस्ता अल्पाइन क्लब ने ओमान की नधीरा अहमद अब्दुल्ला अल हार्थी और नेपाल के पुर बहादुर गुरूंग के रूप में की.

काराकोरम रेंज में 8,047 मीटर ऊंची चोटी पर गुरुवार को हिमस्खलन की खबर मिलने के बाद टीम के लिए खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था.नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ब्रॉड पीक पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले निर्मल पुर्जा समेत सभी पर्वतारोहियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है.पर्वतारोहण के लिए काम करने वाली संस्था अल्पाइन क्लब ने कहा कि उसे ₹ब्रॉड पीक पर पर्वतारोहियों के एक दल पर गुरुवार दोपहर के आसपास आए हिमस्खलन की बेहद चिंताजनक सूचना मिली है.काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित ब्रॉड पीक की ऊंचाई 8,047 मीटर है.बयान के अनुसार, शुरूआती जानकारी के मुताबिक अभियान दल में 10 पर्वतारोही शामिल थे.इनमें निर्मल पुर्जा के नेतृत्व में पांच नेपाली पर्वतारोही, पाकिस्तान के सोहेल साखी, ओमान का एक पर्वतारोही, एक अमेरिकी, मिस्टर वांग नामक एक चीनी नागरिक और एक अन्य विदेशी पर्वतारोही शामिल थे.ट्रेकिंग कंपनी मूविंग माउंटेन्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि अमेरिकी पर्वतारोही मैलोरी गीस, सोहेल साखी के साथ ब्रॉड पीक अभियान में शामिल थीं. 27 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट में निर्मल पुर्जा ने लिखा था कि यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था.निर्मल पुर्जा ने 2019 में दुनिया की 8,000 मीटर (26,300 फुट) से अधिक ऊंचाई वाली सभी 14 चोटियों को महज छह महीने से कुछ अधिक समय में फतह कर इतिहास रच दिया था.उनकी इस उपलब्धि पर आधारित नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री '14 पीक्सः नथिंग इज इम्पॉसिबल' भी बनी थी.

निर्मल पुर्जा के नेतृत्व में ही 10 नेपालियों ने 17 जनवरी को सर्दी में पहली बार 28,251 फुट ऊँचे के2 को फतह किया था. के2 काराकोरम रेंज का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है, लेकिन इसे सबसे खतरनाक माना जाता है.सर्दी के मौसम में निर्मल पुर्जा की टीम से पहले कोई नहीं चढ़ पाया था. इस टीम में निर्मल पुर्जा एकमात्र थे, जो नेपाल के चर्चित शेरपा समुदाय से नहीं थे. निर्मल मगर (नेपाल का एक समुदाय) हैं और ब्रिटिश गोरखा ब्रिगेड में सैनिक थे.निर्मल पुर्जा मुश्किल से पाँच फुट के हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया के ऊँचे से ऊँचे पर्वतों को अपने छोटे कदमों से लांघ दिया है.उनके नाम जो रिकॉर्ड हैं, वो बेमिसाल हैं. यहाँ तक कि के2 पर बसंत और गर्मी के मौसम में भी चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन निर्मल की टीम ने इसे सर्दी के मौसम में लाँघ दिया.के2 पर चढ़ने की कोशिश करने वालों में से लगभग हर छह में से एक की मौत हो जाती है, जबकि माउंट एवरेस्ट में मौत का औसत लगभग 34 में एक है.इसी से समझा जा सकता है कि यह कितना खतरनाक है. जिस दिन निर्मल की टीम ने के2 समिट पूरा किया, उसी दिन स्पेन के पर्वतारोही सेरजी मिन्गोटे ने के2 पर पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ दिया था. मिंगोटे इससे पहले दुनिया के 10 सबसे ऊँचे पर्वतों पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ चुके थे. मध्य एशिया में सभी 14 वैसे पर्वत हैं, जिनकी ऊँचाई 8,000 मीटर से ज्यादा है.निर्मल का जन्म धौलागिरी के पास हुआ. यह दुनिया का सातवाँ सबसे ऊँचा पर्वत है. लेकिन निर्मल पले-बढ़े नेपाल में चितवन ज़िले के समतल में. निर्मल 18 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी ब्रिगेड के गोरखा में भर्ती हो गए.

अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट, मध्य पूर्व से किसी भी वक्त निकलने के लिए रहें तैयार

अमेरिकी सरकार ने मध्य पूर्व में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और क्षेत्र में तनाव बढ़ने की स्थिति में वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की अपील की है.

यह अपील ऐसे समय में आई है, जब अमेरिकी मीडिया में खबरें हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सप्ताहांत के दौरान ईरान पर नए और अधिक तेज हमलों की योजना बना सकते हैं.अपने सुरक्षा अलर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, ₹मध्य पूर्व के बाहर मौजूद अमेरिकी राजनयिक प्रतिष्ठानों समेत अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान और उसका समर्थन करने वाले समूह दुनिया भर में अमेरिका और उससे या उसके नागरिकों से जुड़े अन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं.इससे पहले ईरान ने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया था और कहा था कि उसके साथ सहयोग करने वाला कोई भी क्षेत्रीय देश ₹युद्ध की लपटों में घिर जाएगा. शनिवार को जारी अमेरिकी सुरक्षा अलर्ट में कहा गया, ₹मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए और उड़ानें रद्द होने, समय-समय पर हवाई क्षेत्र बंद होने के साथ ही यात्रा में संभावित बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए.अलर्ट में कहा गया, ₹क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी नागरिक वहां से निकलने पर विचार करें या अगर तनाव बढ़े तो तुरंत रवाना होने के लिए तैयार रहें. वहीं मध्य पूर्व से बाहर मौजूद अमेरिकी नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा या यहां से होकर यात्रा करने के अपने फैसले पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए.बहरीन, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समेत पूरे मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी दूतावासों ने अमेरिकी नागरिकों के लिए यह सुरक्षा अलर्ट फिर से जारी किया और अचानक तनाव बढ़ने की चेतावनी दी.इससे पहले अमेरिकी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप इसी सप्ताहांत ईरान पर नए हमलों का आदेश दे सकते हैं.ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हुए अमेरिका और इसराइल अब तक के सबसे भीषण बमबारी अभियानों में से एक की योजना बना रहे थे.अमेरिका में बीबीसी के मीडिया साझेदार सीबीएस न्यूज को कई सूत्रों ने यह जानकारी दी.सीबीएस न्यूज ने बताया कि सूत्रों के अनुसार यह योजना शुक्रवार को हुई ट्रंप की कैबिनेट बैठक के दौरान सामने आई.एक सूत्र ने कहा कि व्हाइट हाउस के कुछ राजनीतिक सलाहकार इस योजना के कड़े विरोध में थे.कैबिनेट बैठक के दौरान, जब पत्रकार अभी भी कमरे में मौजूद थे, तब ट्रंप को यह कहते हुए सुना गया, ₹हम उन पर (ईरान) बहुत जोरदार हमला करेंगे. एक समय ऐसा आएगा जब वे कहेंगे कि अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते.

रावलाकोट-मीरपुर में हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत की इस संगठन ने की आलोचना, भारत भी बोला

नेपाल के मधेश इलाके में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, तीन की मौत

नेपाल के मधेश इलाके के कई ज़िलों में भड़के सांप्रदायिक तनाव के बाद तीन लोगों की मौत हो गई है.इन मौतों के बाद मधेश के कई ज़िलों में भारी तनाव पैदा हो गया और कर्फ़्यू लगाना पड़ा.हालांकि सर्वदलीय बैठक के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.बीबीसी की नेपाली सेवा के मुताबिक गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने तनाव प्रभावित सुनसरी और देवानगंज पहुँचकर हालात सामान्य करने की कोशिश की है.यहाँ दो लोगों की मौत हो गई थी. सिरहा में एक शख़्स की मौत हुई है.नेपाल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हिंसा के बाद गुरुवार रात से सुनसरी, सिराहा और धनुषा में कर्फ़्यू लगा दिया गया था.गुरुवार (30 जुलाई) को हिंसा में सिराहा जिले के औराही ग्रामीण नगरपालिका इलाके में रहने वाले में 17 साल के गणेश यादव की झड़प के बाद गोली लगने से मौत हो गई.इससे पहले रविवार को सुनसरी में हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल 20 साल के जयप्रकाश मेहता की बिराटनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.यह हिंसा 26 जुलाई (रविवार) की रात सुनसरी में दो समुदायों की झड़प के बाद शुरू हुई थी. इसमें देवानगंज के 24 साल के ओमप्रकाश मेहता की गोली लगने से मौत हो गई थी बीबीसी की नेपाली की सेवा के मुताबिक शुक्रवार दोपहर तक कोशी प्रांत के सुनसरी, धनुषा और सिरहा के कुछ इलाकों में नारेबाजी और रैलियों की खबरें आईं.गृह मंत्री सुदन गुरुंग की ओर से मृतकों के परिवारों के साथ हुए समझौते में राहत से लेकर जांच तक के मुद्दे शामिल हैं.समझौते में कहा गया है कि नेपाल सरकार मृतकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगी.साथ ही मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपये मुआवजा देगी.उन्होंने कहा कि 26 जुलाई की रात को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.उन्होंने कहा कि देवानगंज-3 में स्थित मदरसे की कानूनी स्थिति और संबंधित मामलों को लेकर तुरंत जांच शुरू होगी.मृतकों के परिवारों वालों से समझौते के बाद गुरुंग ने पत्रकारों से कहा, हमारे देश में अब तक दो धर्मों के लोगों के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है. हम इस समस्या को जड़ से खत्म करने की जरूरत समझते हैं."कई ज़िलों में सार्वजनिक जगहों पर डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. धार्मिक और सार्वजनिक जुलूसों के दौरान हथियार या ऐसी चीजों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, जिनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो सकता है.पिछले रविवार को सुनसरी ज़िले के देवानगंज स्थित कप्तानगंज में दो धार्मिक समूहों के लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था.बीबीसी की नेपाली सेवा के मुताबिक तनाव तब शुरू हुआ जब कांवड़ यात्रा की तैयारी कर रहे कुछ लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के गांव के नजदीक बिजली के खंभों मे झंडे लगा दिए और तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया

'इंसाफ के लिए आवाज उठाते बेटे को गोली मार दी': जानलेवा प्रदर्शनों से घिरे रावलाकोट के अंदर क्या चल रहा है?

डॉ. अनवर का अस्थायी क्लिनिक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रावलाकोट शहर में मुख्य विरोध प्रदर्शन स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित है.एक अतिरिक्त बेडरूम चिकित्सा सामग्री रखने के लिए अलमारी के रूप में इस्तेमाल होता है, और बाहर लाल तिरपाल से ढका एक बिस्तर है.बिस्तर पर शफकत हुसैन लेटे हुए हैं. हुसैन के सीने में गोली लगी है. जिस चादर पर वह लेटे हैं, वह पहले से ही घायल हुए लोगों के खून से सनी हुई है. वह मरणासन्न हैं.पिछले दो महीनों में, सुरक्षा अधिकारियों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के बीच झड़पों में पूरे इलाके में दर्जनों लोग मारे गए हैं.

'40 वर्ष से अधिक आयु के बहुत कम मरीज देखे'

45 लाख की आबादी वाले इस इलाके में इस समय चुनाव हो रहे हैं.बीबीसी रावलाकोट में प्रवेश पाने वाला और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में मौजूद लोगों से बात करने वाला पहला मीडिया संगठन है.डॉ. अनवर समेत जिन लोगों से इस रिपोर्ट के लिए हमने बात की, उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए उनका नाम बदल दिया है.उन्होंने बीबीसी को बताया, हमारे पास प्राथमिक इलाज देने लायक सामान है. हम खून बहना रोक सकते हैं, घाव साफ करके पट्टी कर सकते हैं और शरीर में कम गहराई तक गई गोली निकाल सकते हैं. लेकिन जिन लोगों के सीने, पेट, सिर या शरीर के दूसरे अहम अंगों में गंभीर चोट है, उन्हें बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है. अनवर आगे कहते हैं, अगर एक ही समय में इतने सारे मरीज आ जाएं तो बड़े-बड़े अस्पतालों को भी परेशानी होगी.डॉक्टर का कहना है कि 27 जुलाई से क्लिनिक में लगभग 50 से 60 गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज किया गया है, और उन्होंने खुद से गोली लगने से घायल 15 से 20 लोगों का इलाज किया है. प्रदर्शनकारी मुख्य अस्पताल जाने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी. अधिकारियों ने इस दावे को गलत बताया है.डॉक्टर अनवर कहते हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनमें से अधिकांश 15-16 वर्ष से लेकर 32-35 वर्ष की आयु के युवा हैं. मैंने 40 वर्ष से अधिक आयु के बहुत कम मरीज देखे हैं.हुसैन के बिस्तर के पास उनके दोस्त अली हैं. वह अपने शॉल से अपने आंसू पोंछ रहे हैं. अली बताते हैं, ₹हमने तो बस सस्ती कीमत पर आटा, बिजली और अपने बुनियादी अधिकार मांगे थे,वह सिसकते हुए अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इसके बदले हमारे भाइयों को मारा जा रहा है. हमारा गुनाह क्या था? हम पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं?जेएएसी के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन उनके अधिकारों के लिए हैं, जिनमें बिजली की कीमतें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी चिंताएं शामिल हैं.अक्तूबर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकारों के साथ हस्ताक्षरित समझौता इसी उद्देश्य से किया गया था. जेएएसी का कहना है कि इसे लागू नहीं किया गया है. स्थानीय सरकार इससे असहमत है. उनका कहना है कि जेएएसी एक हथियारबंद समूह है और इसका मकसद चल रहे चुनावों में बाधा डालना है. वे प्रदर्शनकारियों को क्षेत्रीय राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद तक मार्च करने देने को तैयार नहीं हैं. जून में जेएएसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इस संगठन को विदेशी वित्त पोषित आतंकवादी करार दिया गया है.जेएएसी इस आरोप को खारिज करते हुए कहते हैं कि वे शांतिपूर्ण हैं. उनका कहना है कि उन्हें विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय से फंड मिलता है, भारत से नहीं.उनका कहना है कि हिंसा शुरू करने के बजाय वे पीड़ित हैं और पाकिस्तानी सुरक्षा बल उन पर गोलीबारी कर रहे हैं. इंटरनेट बंद होने और सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण सूचना हासिल करना मुश्किल हो गया है.शहर पहुंचने के बाद, बीबीसी ने कई परिवारों से बात की, जिन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शनों में गोली लगने से उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया.अस्मा ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके इकलौते बेटे को गोली मार दी गई है, तब वह खुद भी विरोध प्रदर्शन में मौजूद थीं.उन्होंने कहा, हम तो बस अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे. हम आतंकवादी नहीं हैं. कोई भी मां इससे बेहतर बेटे की कामना नहीं कर सकती. वह जानते थे कि जोखिम हैं, लेकिन उनका मानना था कि न्याय के लिए खड़े होना महत्वपूर्ण है. वह कहा करते थे कि इंसाफ के लिए मरना सम्मान की बात है. सलमान ने अपने भाई को खो दिया.

उन्होंने कहा, वह परिवार में सबसे छोटा था और सभी उसे प्यार करते थे. यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है. साथ ही मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने जनता के अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी. वे किसी से लड़ नहीं रहे थे और न ही किसी पर हमला कर रहे थे.अयूब पहले सशस्त्र बलों में नौकरी कर चुके हैं और उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था.उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान सरकार या सेना को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि पाकिस्तान सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अर्धसैनिक बलों को बुलाने का आदेश उन्होंने ही दिया था.उन्होंने कहा, मैं एक सेवानिवृत्त सैनिक हूं. मैंने जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में मार्शल लॉ देखा है. लेकिन मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा. मेरी राय में, यह घोर अन्याय है. मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया था. प्रदर्शनकारियों में से किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया था.

'हत्या के लिए एक करोड़ का इनाम देने का वादा'

पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह उन आरोपों को खारिज करती है कि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की.अधिकारियों ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो कानून प्रवर्तन कर्मियों पर हमले में शामिल थे, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे थे या वैध अधिकार में बाधा डाल रहे थे.बीबीसी ने इस इलाके में खाद्य पदार्थों की कमी देखी. हमने देखा कि कई प्रदर्शनकारी आपस में अपना भोजन बाँट रहे थे.

सऊदी अरब के बाद अब कुवैत से पाकिस्तान का रक्षा समझौता, भारत के लिए क्या हैं मायने

पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के तीन साल बाद, कुवैत ने समझौते को कानूनी रूप देने की मंजूरी दे दी है. कुवैत में पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक, यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग का एक ढांचा तैयार करता है और सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी, रसद सहायता, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और अनुभव के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है.इसका मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रिसर्च और 'मिलिटरी इंस्टीट्यूशन संबंधों को मजबूत' करना है. कुवैत में पाकिस्तान के राजदूत जफर इकबाल ने कुवैती अखबार अल-जरीदा को बताया कि समझौते पर 11 जून 2023 में हस्ताक्षर किए गए थे और अब इसका अध्यादेश जारी होने के साथ प्रक्रिया पूरी हो गई है.

इकबाल के अनुसार, यह समझौता 'रक्षात्मक प्रकृति' का है और इसमें आपसी समझ, पेशेवर सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है.कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबाह ने हाल ही में एक आधिकारिक दौरे पर इस्लामाबाद की यात्रा की थी और तभी उम्मीद जताई जा रही थी कि समझौता अब अमल में आएगा.

जून 2023 में समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में पाकिस्तान के राजदूत मलिक मुहम्मद फारूक और कुवैती रक्षा मंत्रालय में संयुक्त योजना के निदेशक ब्रिगेडियर जनरल फवाज खुदेर मुहम्मद अल-हरबी शामिल थे. उस समय, दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की थी कि यह समझौता 'दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत' करेगा.

तीन साल बाद कुवैत सरकार की ओर से जारी अध्यादेश को अल-अन्बा अखबार ने प्रकाशित किया है. इस अध्यादेश में कहा गया है, ₹कुवैत सरकार और पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए 11 जून, 2023 को कुवैत में हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी जाती है.इस अध्यादेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कुवैती मंत्री अपने-अपने ज़िम्मेदारी के क्षेत्रों के दायरे में इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हैं. इस समझौते में 12 अनुच्छेद शामिल हैं.समझौते में मिलिटरी ट्रेनिंग, रसद सेवाएं, सैनिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, मिलिटरी टेक्नोलॉजी में सहयोग और सैन्य खुफिया सहयोग शामिल है.तालमेल के लिए एक संयुक्त सैन्य समिति के गठन का प्रावधान है, जिसकी बैठक साल में एक बार होगी.

इस समझौते के प्रावधान दोनों देशों के बीच अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों से पैदा होने वाले अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को प्रभावित नहीं करते हैं.दोनों पक्षों की लिखित सहमति से किसी भी समय समझौते में संशोधन करने की अनुमति देता है.समझौते को लागू करने की ज़िम्मेदारी दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की है.

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सितंबर 2025 में एक 'संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौता' हुआ था, जिसके अनुसार 'किसी भी देश के खिलाफ कोई भी विदेशी आक्रमण दोनों देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा.'अप्रैल 2026 में, सऊदी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि इस समझौते के ढांचे के भीतर, लड़ाकू जेट और सहायक विमानों सहित एक पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी सऊदी अरब के किंग अब्दुलअजीज हवाई अड्डे पर पहुंच गई है.

लेकिन कुवैत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.रक्षा विश्लेषक अमिद महमूद शाह ने बीबीसी को बताया, ₹सऊदी अरब के साथ हुए समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और इसके विपरीत भी. लेकिन कुवैत के साथ हुए समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और यह प्रशिक्षण, रसद, अनुभव, प्रौद्योगिकी, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और रक्षा उद्योगों के विकास पर अधिक केंद्रित है.कुवैत में पाकिस्तान के राजदूत जफर इकबाल ने अल-जरीदा अखबार को बताया कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध 1980 के दशक की शुरूआत से चले आ रहे हैं और अब इन्हें नए घटनाक्रमों के अनुरूप एक संगठित प्रारूप में औपचारिक रूप दिया गया है.

फरवरी से ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के बीच चल रही जंग के दौरान खाड़ी देशों को कई जवाबी हमलों का सामना करना पड़ा है.ईरान ने बार-बार कहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं. कुवैती सेना ने बार-बार ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की भी सूचना दी है.कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ के रूप में इस्लामाबाद की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है.सिंगापुर स्थित डिफेंस रिसर्चर अब्दुल बासित ने बीबीसी से कहा, ₹क्षेत्र में अमेरिकी भू-राजनीतिक प्रभाव घट रहा है और अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर खाड़ी देशों का भरोसा भी कम हो रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सैन्य अभियान के बावजूद, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है और होर्मुज स्ट्रेट में यातायात सामान्य नहीं हो पाया है.उनके अनुसार, ₹दोहा में हमास नेताओं पर इसराइली हमला एक निर्णायक मोड़ था जिसने दिखाया कि अधिक उपकरण खरीदने से जरूरी नहीं कि सुरक्षा सुनिश्चित ही हो, बल्कि पारस्परिक सुरक्षा गारंटी अधिक महत्वपूर्ण हैं.

अब्दुल बासित

अब्दुल-बासित ने बताया कि फारस की खाड़ी के देश द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं और सऊदी अरब और अमेरिका की सहमति से यह प्रक्रिया एक 'नई क्षेत्रीय व्यवस्था' को आकार दे रही है.उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सुरक्षा बोझ को कम करने की कोशिश कर रहा है,

रायपुर में 191 किलो गांजा जब्त, बंगाल के 2 तस्कर गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कमिश्नरेट पुलिस की तेलीबांधा थाना टीम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (अठळऋ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक से 191 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 19 लाख 10 हजार रुपये बताई जा रही है। मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (ठउढर) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई तेलीबांधा थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस और एएनटीएफ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक अशोक लीलैंड ट्रक के जरिए बड़ी मात्रा में गांजा रायपुर होते हुए अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और अग्रसेन धाम के पास सर्विस रोड पर घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोक लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके भीतर छिपाकर रखा गया 191 किलो गांजा मिला। पुलिस ने मौके पर ही पूरी खेप को जब्त कर लिया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 19.10 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे अशोक लीलैंड ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उनकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद लाल और मोहम्मद रूस्तम के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की यह बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस तस्करी के पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा बीते कुछ समय से नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गांजा, अफीम, चरस और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए थाना पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इसी अभियान के तहत यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साय की बड़ी घोषणा, माघ पूर्णिमा पर रहेगा सरकारी अवकाश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत समाज, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास के विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में घोषणा की कि अब हर वर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दिन प्रदेशभर में शराब और अन्य मादक पेय पदार्थों की बिक्री भी पूरी तरह बंद रहेगी। सरकार का उद्देश्य गुरु रविदास के आदर्शों, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक मूल्यों को सम्मान देना है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। सीएम साय ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार के राज्य अलंकरण सम्मान में अब एक प्रतिष्ठित पुरस्कार संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने समाज में समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी तक उनके संदेश को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रायपुर में एक प्रमुख चौक का नाम संत रविदास के नाम पर रखा जाएगा,

तालाब किनारे चौकीदार की संदिग्ध मौत, शव मिलने से मचा हड़कंप

रायपुर। रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र के टोकरो गांव में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के तालाब के पास चौकीदारी का काम करने वाले एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और तरह-तरह की चचाएं शुरू हो गईं। सूचना मिलने पर अभनपुर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हत्या की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान परमेश्वर सिदार (30 वर्ष) पिता जलसिंग सिदार, निवासी ग्राम तोरला, जिला बरगढ़ (ओडिशा) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार परमेश्वर पिछले करीब छह महीने से टोकरो गांव स्थित तालाब में चौकीदार के रूप में कार्यरत था। वह तालाब की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार वह रोजाना अपने काम पर नियमित रूप से मौजूद रहता था और किसी तरह के विवाद की जानकारी सामने नहीं आई थी। ऐसे में अचानक उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने तालाब के पास उसका शव पड़ा देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना से जुड़े किसी भी अहम सुराग तक पहुंचा जा सके। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह हत्या का मामला है तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभनपुर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को सुरक्षित किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर फोरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

कुएं में गिरने से महिला की मौत पर उठे सवाल

आरंगः छत्तीसगढ़ के आरंग में शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पिता ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों का आरोप है कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि पति के अवैध संबंधों के चलते की गई एक सोची-समझी हत्या है। यह पूरा मामला आरंग थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 का है। रामधार सोनकर द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार, उनकी पुत्री पुष्पा सोनकर का विवाह लगभग 20 साल पहले गुढ़ियारी पारा निवासी रामानंद सोनकर के पुत्र भोला सोनकर के साथ हुआ था। इस दंपती के चार बच्चे हैं। शिकायत में बताया गया है कि पिछले तीन सालों से आरोपी भोला सोनकर का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा है, जिससे उसका एक वर्ष का बच्चा भी है। इसी बात को लेकर भोला अक्सर पुष्पा और उसके बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट करता था। साथ ही जान से मारने की धमकियां देता था। मृतका की 18 वषीर्या बेटी के अनुसार, 30 जुलाई को आरोपी भोला सोनकर घर नहीं लौटा था।

दिनदहाड़े ज्वेलर्स दुकान में 4.45 लाख की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी बाजार में स्थित एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स दुकान में दिनदहाड़े हुई लाखों रुपये की चोरी की वारदात ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है। शातिर चोर ने ग्राहक बनकर दुकान में प्रवेश किया और दुकानदार को बातों में उलझाकर लाखों रुपये के सोने के ईयर रिंग लेकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे बाजार में हड़-कंप मच गया। सूचना मिलते ही नगरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। यह पूरा मामला नगरी थाना क्षेत्र के नगरी बाजार स्थित नवकार ज्वेलर्स का है। जानकारी के अनुसार वारदात के समय दुकान में सामान्य रूप से कारोबार चल रहा था। इसी दौरान एक युवक ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचा और उसने सोने के ईयर रिंग देखने की इच्छा जताई। दुकानदार ने उसे विभिन्न डिजाइन के ईयर रिंग दिखाने शुरू किए। आरोपी पूरे आत्मविश्वास के साथ जेवरों को देखता रहा और बीच-बीच में दुकानदार से अलग-अलग डिजाइन और कीमत के बारे में सवाल पूछता रहा, जिससे किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से पूरी तैयारी के साथ दुकान में आया था। उसने बड़ी ही चालाकी से दुकानदार का ध्यान दूसरी ओर भटकाया। जैसे ही दुकानदार कुछ क्षण के लिए अन्य काम में व्यस्त हुआ, आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए काउंटर पर रखे 9 नग सोने के ईयर रिंग चुपचाप अपने कब्जे में कर लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद वह बिना किसी हड़बड़ी के दुकान से बाहर निकला और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब दुकान मालिक ने काउंटर पर रखे जेवरों की गिनती की तो उनके होश उड़ गए। काउंटर से 9 सोने के ईयर रिंग गायब थे। पहले तो उन्होंने दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ पूरे परिसर में तलाश की, लेकिन जेवरों का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ चोरी की घटना हो चुकी है। तत्काल आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और बाजार में आरोपी की तलाश की गई, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोरी हुए 9 सोने के ईयर रिंग की कुल कीमत करीब 4 लाख 45 हजार रुपये बताई जा रही है। इतनी बड़ी चोरी की खबर फैलते ही बाजार के अन्य व्यापारी भी दुकान पर पहुंच गए। व्यापारियों ने घटना पर चिंता जताते हुए बाजार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। उनका कहना है कि भीड़भाड़ वाले बाजार में इस तरह की वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। घटना की सूचना मिलने के बाद नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान का निरीक्षण किया। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। फुटेज में आरोपी की गतिविधियों और हुलिए की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास की अन्य दुकानों और बाजार क्षेत्र में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि आरोपी के आने-जाने के रास्ते और उसकी पहचान के संबंध में अहम सुराग मिल सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया है,

महानदी के तट पर आस्था का महाकुंभः बनारस की तर्ज पर गूंजे वैदिक मंत्र, दिव्य बनेगा रुद्रेश्वर धाम

रायपुरः सावन के पहले सोमवार की संध्या धमतरी की चित्रोत्पला महानदी का तट केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और अध्यात्म का सजीव संगम बन गया। काशी की तर्ज पर जब 108 दीपों की स्वर्णिम आभा के बीच पहली बार भव्य ह्यमहानदी गंगा आरतीह्न का शुभारंभ हुआ, तो शंखनाद, वैदिक मंत्रों और घंटियों की गूंज से पूरा रुद्री घाट अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। धमतरी युवा ब्रिगेड और श्री रुद्रेश्वर महादेव परिवार के इस ऐतिहासिक प्रयास ने नगर की सांस्कृतिक चेतना को नई दिशा दी है। अब जनआस्था का यह पावन पर्व सावन के प्रत्येक सोमवार को महानदी के तट पर सजने जा रहा है। भक्ति के इस आध्यात्मिक वातावरण के बीच धमतरी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की शुरूआत हुई है। प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने प्राचीन रुद्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए 20 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। इस परियोजना के माध्यम से रुद्रेश्वर धाम को एक ऐसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की धरोहर को राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा। तीन चरणों में बदलेगा रुद्रेश्वर धाम का स्वरूपयह मास्टर प्लान प्राचीन स्थापत्य कला और आधुनिक जनसुविधाओं का बेहतरीन संतुलन प्रस्तुत करता है। मंदिर की पारंपरिक भारतीय स्थापत्य शैली को संरक्षित रखते हुए भव्य मुख्य प्रवेश द्वार, आकर्षक शिखर, तोरण, दीप स्तंभ और विशाल नंदी प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा।श्रद्धालुओं के लिए चौड़े पैदल मार्ग, विश्राम गृह, प्रसाद व स्मृति केंद्र, फूड कोर्ट, सुरक्षित घाट और डिजिटल सूचना प्रणाली की व्यवस्था होगी। परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एआई (अक) आधारित हेल्थ कियोस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह परिसर में उद्यान, सांस्कृतिक मंडप, रिवर फ्रंट कॉटेज, ओपन एयर स्टेज और भविष्य की 'मैरीन ड्राइव' की तर्ज पर एक सुरम्य तट विकसित किया जाएगा।पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा पार्किंग, ईवी (एश) चार्जिंग स्टेशन, वर्षा जल संचयन और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन लागू किया जाएगा। विधायक ओंकार साहू, महापौर जगदीश रामू रोहरा, कलेक्टर और पूर्व विधायक रंजना साहू सहित कई गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति में शुरू हुआ यह आयोजन धमतरी के सामाजिक और आर्थिक विकास के नए युग का प्रतीक है।

महानदी गंगा आरती की अविरल धारा और रुद्रेश्वर धाम का समग्र विकास मिलकर न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और जनसहभागिता को भी एक नया आयाम देंगे।

रक्तदान और मानव सेवा की मिसाल, आरक्षक को मिला 'छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान

रायगढ़ः रक्तदान और निस्वार्थ मानव सेवा के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए रायगढ़ पुलिस के आरक्षक रवि श्रीवास को प्रतिष्ठित *'छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2026'* से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 2 अगस्त को रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल परिसर में हेल्पिंग हैंड्स क्लब फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। समारोह में प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा प्रदेश के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के हाथों आरक्षक रवि श्रीवास को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से समाज सेवा, रक्तदान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवियों को भी सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि आरक्षक रवि श्रीवास अपनी पुलिस ड्यूटी के साथ-साथ लंबे समय से श्री साईं रक्तदान समिति के माध्यम से रक्तदान एवं मानव सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने न केवल स्वयं नियमित रक्तदान किया है, बल्कि हजारों युवाओं और नागरिकों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने, आपातकालीन परिस्थितियों में रक्तदाताओं का नेटवर्क तैयार करने तथा रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आरक्षक रवि श्रीवास और उनकी समिति का मानना है कि रक्तदान महादान केवल एक संदेश नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद को जीवनदान देने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। उनके प्रयासों से अनेक गंभीर मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों, प्रसूताओं एवं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सका है। मानवता की सेवा के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिलाई है। इस सेवा अभियान को आगे बढ़ाने में उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह का सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। रायगढ़ पुलिस द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी को भी उनके कार्यों से नई प्रेरणा मिली है। समाजहित में किए जा रहे उनके योगदान की विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं जनसेवी मंचों पर समय-समय पर सराहना होती रही है।

किडनी-लिवर की रिपोर्ट को लेकर डरे पवन सिंह:खुद डॉक्टर बन इंटरनेट पर मेडिकल टर्म्स सर्च किए, मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर फेंकी

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह अपनी सेहत और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर काफी हैं। आगामी शो 'भोजपुरी बवाल' के सेट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह अपनी किडनी और लिवर की टेस्ट रिपोर्ट को लेकर चिंता जताते दिख रहे हैं। अपनी ज्यादा सोचने (ओवरथिंकिंग) की आदत की वजह से पवन सिंह डॉक्टर की सलाह का इंतजार करने के बजाय खुद ही इंटरनेट और एलेक्सा पर मेडिकल टर्म्स सर्च करने लगे। यह शो 2 अगस्त से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रहा है।

रिपोर्ट सही आएगी ना? टीम से पूछते दिखे पवन सिंह वीडियो में पवन सिंह अपने साथियों के साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। वे परेशान होकर पूछते हैं, ₹रिपोर्टवा सही आई ना रे?₹ इस पर उनकी टीम के सदस्य उन्हें दिलासा देते हैं कि लाखों लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा।

हालांकि, पवन सिंह अपनी ओवरथिंकिंग की आदत को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने की बीमारी है। जैसे ही टीम का एक सदस्य हाथ में रिपोर्ट की फाइल लेकर आता है, पवन सिंह तुरंत पूछते हैं कि इसमें कोई डराने वाली बात तो नहीं है। एलेक्सा से पूछा ळछउ और हीमोग्लोबिन का मतलब रिपोर्ट खुद समझने की कोशिश में पवन सिंह की टीम फोन पर एलेक्सा से मेडिकल शब्दों के मतलब पूछने लगती है। जब टीम ने 'ळछउ' का मतलब पूछा, तो एलेक्सा ने इसका जवाब ह्यटेंडर लविंग केयरद्ध दिया। यह सुनकर पवन सिंह और उनकी पूरी टीम सोच में पड़ गई। इसके बाद पवन सिंह ने किडनी और लिवर की रिपोर्ट देखते हुए हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा। रिपोर्ट देखकर भड़के, टेबल पर पटक दी फाइल फाइल देखते समय पवन सिंह खुद ही डॉक्टर की तरह रिपोर्ट का विश्लेषण करने लगे। उन्होंने रिपोर्ट में 10,700 का आंकड़ा देखकर कहा कि जब नॉर्मल रेंज 6,000 से 15,000 के बीच होती है, तो यह रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि इसे काला (हाईलाइट) क्यों किया गया है। रिपोर्ट में लिखे मेडिकल शब्दों को समझ न पाने और असमंजस की स्थिति बनने पर पवन सिंह इतने चिढ़ गए कि उन्होंने फाइल टेबल पर पटक दी। डॉक्टर के सवाल पर बोले- पता नहीं एलेक्सा मौसी है या भौजी माहौल में हंसी-मजाक तब बढ़ गया जब डॉक्टर का फोन आया। पवन सिंह ने फोन पर डॉक्टर से कहा कि रिपोर्ट उन्होंने खुद देख ली है और एलेक्सा ने भी सब बता दिया है। इस पर जब डॉक्टर ने पूछा कि ₹मुझे बताओ यह एलेक्सा कौन है?

सबकुछ खत्म हो गया', देवोलीना की मां असम की बाढ़ में फंसी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां असम के बाढ़ में फंसी हुई हैं और वहां सबकुछ बर्बाद हो चुका है। एक्ट्रेस ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित नजीरा में उनका पूरा परिवार फंसा है। फैंस देवोलीना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करके असम में आई भयानक बाढ़ पर रिएक्ट किया है। अपने परिवार के हालात के बारे में बात करते हुए वह भावुक हो गईं और रो पड़ीं। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां अभी बाढ़ से प्रभावित नजीरा में फंसी हुई हैं, जिससे वह बहुत परेशान और बेबस महसूस कर रही हैं। अपना दुख जाहिर करते हुए देवोलीना ने बताया कि वह अब तक चुप क्यों थीं। उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि अगर वह पहले इस बारे में बात करतीं, तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पातीं। हालात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत अफसोस है।

सलमान खान बोले- जेल में 70 लोगों के साथ एक बैरक में रहता था, इंडियन कमोड था, गंदगी ऊपर तक भरी रहती थी

सलमान खान ने हाल ही में 'अलायंस' में बताया है कि उनके जेल का एक्सपीरियंस कैसा था। सलमान की बातें सुनकर कंटेस्टेंट्स भी भावुक हो गए। सोहेल खान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जेल में 70 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहते थे और एक ही कमोड था।

सलमान खान ने बताईं जेल की बातें

सलमान खान जब भी पब्लिक में आते हैं, तो अक्सर चर्चा में आ जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिनमें वे कमजोर नजर आ रहे थे, जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई। लेकिन आज सलमान खान के वायरल होने की एक और वजह है, और वह है के शो 'अलायंस' में उनकी गेस्ट अपीयरेंस। वे अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए इस शो में आए हैं। शो के लेटेस्ट प्रोमो में उन्हें अपने मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। नए प्रोमो के अनुसार, सलमान खान को अपने जेल के दिनों को याद करते हुए और उस कठिन दौर से कैसे उबरे, यह बताते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, 'बहुत सालों पहले जब जेल गया था तो हमारे सामने सलाखें थीं। इतने छोटे से कमरे में 50-60-70 लोग थेङ्ग एक ही बाथरूम था, इंडियन कमोड था, कभी छिपकली थीं और उससे भी बढ़कर गंदगी यहां तक भरी हुई थी।'सलमान और सोहेल की बातें प्रोमो में सलमान खान ने सोहेल खान और सीमा सचदेह के तलाक के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने बड़प्पन दिखाते हुए सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली, लेकिन परिवार के एक सदस्य के तौर पर उन्होंने देखा है कि शादी टूटने के बाद उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

सलमान ने सोहेल से खुलकर बात की, उन्हें हिम्मत बंधाई और साथ ही अपनी एक्स-वाइफ सीमा के साथ उनके रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने सोहेल से कहा, 'क्या तुम अब भी सीमा की बात मान रहे हो?

मेरे नेक भाई ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लेकिन एक भाई के तौर पर मैं जानता हूं

लगातार बंद होती रहीं फिल्में, स्टारकिड होने का भी नहीं मिला फायदा, फिर नेगेटिव रोल रातोंरात चमकी किस्मत

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता, निमार्ता और निर्देशक अरबाज खान का फिल्मी सफर जितना आसान दिखता है, उतना रहा नहीं. फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उन्हें करियर की शुरूआत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा.नेगेटिव रोल के जरिए उन्हें बड़ी पहचान मिली थी.

4 अगस्त 1967 को जन्मे अरबाज खान, मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे और सलमान खान व सोहेल खान के भाई हैं. हालांकि फिल्मी माहौल में बड़े होने के बावजूद उन्हें अपने करियर की शुरूआत में काफी संघर्ष करना पड़ा. बहुत कम लोग जानते हैं कि अरबाज का बॉलीवुड डेब्यू 1992 में फिल्म 'फुटपाथ' से होने वाला था. इसी फिल्म के लिए उन्होंने उस समय की चर्चित फिल्म 'खिलाड़ी' का ऑफर छोड़ दिया था. लेकिन बदकिस्मती से 'फुटपाथ' बीच में ही बंद हो गई और उनका डेब्यू टल गया. बाद में 'खिलाड़ी' रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई. इसके बाद उनकी फिल्म 'राम' भी पूरी नहीं हो सकी. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन निमार्ता मंसूर सिद्दीक और सोहेल खान के बीच विवाद के चलते इसे रोक दिया गया. फिल्म का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा शूट हो चुका था. बाद में इसका टाइटल सॉन्ग निमार्ता फिरोज नाडियाडवाला ने खरीदकर अपनी फिल्म 'राम शास्त्र' में इस्तेमाल किया. इतना ही नहीं, 1993 में अरबाज ने जीनत अमान के साथ हॉलीवुड फिल्म 'फैटल अट्रैक्शन' का हिंदी रीमेक बनाने की भी योजना बनाई थी. इस प्रोजेक्ट में वह अभिनय के साथ-साथ निर्माण भी करने वाले थे, जबकि निर्देशन अब्बास-मस्तान के जिम्मे था. हालांकि यह फिल्म भी कभी शुरू नहीं हो सकी. लगातार प्रोजेक्ट बंद होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. लेकिन 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'दरार' ने सब कुछ बदल दिया. इस फिल्म में अरबाज ने एक हिंसक और सनकी पति का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा. इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट विलेन अवॉर्ड भी मिला. यही फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई. इसके बाद अरबाज ने 'प्यार किया तो डरना क्या', 'हलचल', 'हैलो ब्रदर' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों में काम किया. हालांकि निमार्ता के रूप में उन्हें सबसे बड़ी सफलता साल 2010 में आई फिल्म 'दबंग' से मिली. सलमान खान स्टारर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसके बाद उन्होंने 'दबंग 2' का निर्देशन भी किया,

32 धमाकेदार एपिसोड वाली इस वेब सीरीज ने OTT पर 6 सालों से डाल रखा है डेरा..कॉमेडी में सबकी बाप

आज के दौर में सिनेमा लवर्स के लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। कई मूवीज और वेब सीरीज इस समय ऐसी हैं जो डळळ पर सबकी पसंदीदा बनी हुई हैं। लेकिन इनमें से एक सीरीज ऐसी भी है जो पिछले 6 सालों से लगातार लोगों की पसंद ही नहीं उनकी दिलों की धड़कन बन चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इस वेब सीरीज में किसी भी तरह का कोई सस्पेंस नहीं है, किसी भी तरह की कोई मारधाड़ नहीं है, इसके बाद भी यह लोगों को इसकी कहानी और किरदारों के लिए पसंद आ रही है, और लंबे समय से लोगों को हंसा भी रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें कोई बड़ा स्टार भी नहीं है, इसके बाद भी इसे भारत की नंबर 1 सीरीज के तौर पर देखा जा रहा है। आइए इस वेब सीरीज के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं।

जिस वेब सीरीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह पिछले 6 सालों से डळळ पर कब्जा जमाए हुए है। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और इसके अलावा यह वेब सीरीज अपने 32 एपिसोड के लिए जानी जाती है। इसका हर एपिसोड लोगों को हर एक सीन के साथ याद भी हो चुका है, क्योंकि इसे देखा ही इतना गया है, इसी कारण यह वेब सीरीज लोगों की 6 सालों से पसंद रही है और इस समय भी नंबर 1 पर है। वाली यह वेब सीरीज केवल लोगों को हंसा ही रही है, इसके बाद भी इसे लोग इतना पसंद कर रही हैं, यह बार आश्चर्य में सभी को डाल रही है, लेकिन इसकी कहानी के चलते यह कहीं न कहीं लोगों से जुड़ जाती है। इसके अलावा इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें आपको कोई बड़ा सितारा भी नजर नहीं आता है। इसमें ज्यादा चमक धमक भी आपको नजर नहीं आती है। इसके बाद भी यह वेब सीरीज भारत के लोगों के लिए उनकी पसंदीदा है। आइए अब आपको इस वेब सीरीज का नाम बता ही देते हैं। इस वेब सीरीज को सभी ढंल्लूँ८३ के नाम से जानते हैं। अब आपको याद आया होगा, बनराकस के वो हंसी भरे तंज, बिनोद की भैया जी वाली हंसी और सचिव का इस पंचायत में गलती से आने के बाद भी यहाँ रुक जाना। शायद इसी कारण यह कहानी सभी को अपने साथ जोड़ लेती है। इस वेब सीरीज की कहानी भी बेहद ही ज्यादा दमदार है, असल में ढँ४'ी१ं गाँव की सिम्पल सी कहानी इस कहानी को सभी से कनेक्ट करने का मौका देती है। इस कहानी को देखकर सभी को कहीं न कहीं अपना गाँव याद आ जाता है। इसी कारण से लोग इस कहानी के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। इस कहानी में न कोई भारी ॐ१ें, न कोई फालतू का ळद्र२३, बस एक सिम्पल सी दुनिया दिखाई गई है, जो आपको हमारे देश में कहीं भी देखने को मिल जाने वाली है। 3 को देखा जाए तो यह भी 2 साल के बाद यानि 2024 में आया था, इसमें भी 8 एपिसोड थे। इसके बाद पंचायत का सीजन 4 2025 में रिलीज हुआ था, और इसमें भी 8 एपिसोड ही थे। इसका मतलब है कि इस वेब सीरीज के अभी तक 4 सीजन में 32 एपिसोड आ चुके हैं और इसका पांचवा सीजन भी जल्द ही आ सकता है। हालांकि, पंचायत सीजन 5 की स्ट्रीमिंग और रिलीजिंग कब होने वाली है, इसे लेकर मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

जैनिफर विंगेट ने शेयर की हल्दी सेरेमनी की अनसीन फोटोज:पति विलियम संग हरे लहंगे में नजर आईं; करन वाही और हरलीन सेठी भी शामिल हुए

टीवी एक्ट्रेस जैनिफर विंगेट ने अपनी हल्दी सेरेमनी की अनसीन तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ब्रिटेन के बिजनेसमैन विलियम इशमेल संग शादी रचाने के कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अपनी प्री-वेडिंग रस्मों की यादें साझा की हैं।

फ्रेंडशिप डे के मौके पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में जैनिफर के करीबी दोस्त और टीवी एक्टर्स करन वाही, हरलीन सेठी और सहबान अजीम नजर आ रहे हैं। सेरेमनी में जैनिफर हरे रंग के लहंगे में दिखीं, जबकि विलियम ने सफेद रंग की शेरवानी पहनी थी।

लिखा- मेरी हल्दी प्यार से भरी थी जैनिफर विंगेट ने इंस्टाग्राम पर हल्दी सेरेमनी की कई कैंडिड तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि उनकी हल्दी सिर्फ एक फंक्शन नहीं थी, बल्कि प्यार से भरा हुआ एक कमरा थी। जब भी वे इन तस्वीरों को देखती हैं, उन्हें कोई न कोई खूबसूरत लम्हा याद आ जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि वे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतने अच्छे दोस्त मिले। एक्ट्रेस हरलीन सेठी ने भी इस सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा- 'यारी दोस्ती हल्दी' ।यूके में क्रिश्चियन रीति-रिवाज से हुई थी प्राइवेट वेडिंग जैनिफर और विलियम ने हाल ही में यूके के वेस्ट वेल्स में एक निजी समारोह में शादी की थी। शादी की जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया पर एक जॉइंट पोस्ट के जरिए दी थी। अपनी वेडिंग में जैनिफर ने व्हाइट स्ट्रैपलेस गाउन और वेल पहना था। वहीं उनके पति विलियम ने नेवी ब्लू सूट के साथ क्रीम कलर का वेस्टकोट पहना था। दोनों ने अपने परिवार और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक-दूसरे को रिंग पहनाकर शादी की।

कौन हैं जैनिफर के पति विलियम इशमेल? जैनिफर विंगेट के पति विलियम इशमेल सिंगापुर में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं। वे 'एमएचसी डिजिटल ग्रुप' में बिजनेस डेवलपमेंट और ट्रेडिंग के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हैं। विलियम ने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की है। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक से की थी। उनके पास फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेडिंग और बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र का लंबा अनुभव है।

करन सिंह ग्रोवर से हुई थी पहली शादी यह जैनिफर विंगेट की दूसरी शादी है।

दिव्या भारती ने मौत से एक दिन पहले की थी शूटिंग, आखिरी डायलॉग था- मुझे बचाओ! अनीस बज्मी ने सुनाया किस्सा

फिल्ममेकर अनीस बज्मी ने दिव्या भारती को लेकर एक बेहद इमोशनल किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि 05 अप्रैल 1993 को दिव्या की मौत से ठीक एक दिन पहले वह उनके साथ शूटिंग कर रहे थे। उनका आखिरी शॉट और डायलॉग 'मुझे बचाओ' था। अनीस ने बताया कि 'लाडला' के लिए श्रीदेवी को राजी करना कितना मुश्किल था, क्योंकि दिव्या के साथ 95% शूटिंग पूरी हो चुकी थी।

दिव्या भारती, भारतीय सिनेमा की वह खूबसूरत अदाकारा रहीं, जो यदि आज जिंदा होतीं तो शायद ही कोई एक्ट्रेस सफलता के मामले में उनके आस-पास भी फटकतीं। साल 1990 में दिव्या भारती ने तमिल फिल्मों से एक्टिंग डेब्यू किया था। दो साल बाद 1992 में सनी देओल के साथ 'विश्वात्मा' से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया और उसी साल उनकी 12 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। जब 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की मौत हुई, तब उनकी 12 फिल्में रिलीज होनी बाकी थीं। उनमें से एक थी 'लाडला', जिसकी आधी शूटिंग वह कर चुकी थीं। 'लाडला' के राइटर अनीस बज्मी थे। उन्होंने एक ताजा इंटरव्यू में उस आखिरी शूट को याद किया है, जब एक दिन पहले ही वह दिव्या से मिले थे।

दिव्या भारती की मौत साल 1993 में 5 अप्रैल की शाम को वसोर्वा में अपने घर की बालकनी से गिरने से हुई। यह वह खबर थी, जिसने दिव्या भारती के फैंस और पूरी इंडस्ट्री की दिल की धड़कन कुछ पल के लिए रोक दिया था। अनीस बज्मी बताते हैं कि एक्ट्रेस की असमय मौत के बाद 'लाडला' फिल्म को फिर से लिखना पड़ा था। उन्होंने बताया कि इस दुखद घटना का टीम पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि लगभग पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा।

दिव्या भारती के बाद श्रीदेवी के साथ शूट की गई 'लाडला'

अनीस बज्मी बताते हैं कि कैसे श्रीदेवी ने बाद में 'लाडला' में लीड रोल निभाने के लिए हामी भरी, जबकि पहले उन्होंने पहले तमिल और तेलुगू में इसी कहानी को ठुकरा दिया था। साल 1994 में रिलीज हुई 'लाडला' में श्रीदेवी, अनिल कपूर और रवीना टंडन लीड रोल में थे। यह उस साल की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म बनी। यह फिल्म दिव्या भारती के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर शूट की गई थी। दिव्या की मौत की वजह से मुझे अपनी दो फिल्मों - लाडला और अंगरक्षक - की शूटिंग दोबारा करनी पड़ी। मुझे याद है कि हम चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे। दिव्या की मौत से एक दिन पहले ही 4 अप्रैल को हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे।

समरसता का संदेश लेकर सरगुजा पहुंचेगा वाराणसी की पावन माटी युक्त कलश

*** संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के अन्तर्गत जिलेभर में निकलेगी कलश यात्रा**

अम्बिकापुर।

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित ह्यसमरसता संकल्प अभियानह्ल के तहत वाराणसी स्थित संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र माटी युक्त कलश पूरे सरगुजा जिले में समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश लेकर भ्रमण करेगी। अभियान गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आगामी माघ पूर्णिमा तक चलेगा।

राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय भव्य कलश वंदन अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूज्य संतों एवं विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पवित्र कलशों का पूजन किया गया। इसके बाद प्रदेश के सभी 36 संगठनात्मक जिलों के भाजपा जिलाध्यक्षों को पवित्र कलश सौंपे गए तथा मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जिला टोली के साथ पवित्र कलश लेकर अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। यह पवित्र कलश बुधवार को अंबिकापुर पहुंचेगा, जहाँ स्थानीय राम मंदिर में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ स्वागत और पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात यह कलश जिले के विभिन्न मंडलों में भ्रमण कर संत रविदास के समरस समाज के संदेश को जन-जन तक पहुँचाएगा।

इस अवसर पर भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि ह्लसंत शिरोमणि गुरु रविदास केवल एक संत नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के महान प्रेरणास्रोत हैं। उनके विचार आज भी समाज को जोड़ने की शक्ति देते हैं। भाजपा का यह अभियान किसी एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का अभियान है। हम संत रविदास के संदेश को गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचाकर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वाराणसी से आई पवित्र माटी युक्त कलश का जिलेभर में श्रद्धापूर्वक स्वागत किया जाएगा तथा इसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को संत रविदास के आदर्शों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यह अभियान सामाजिक एकता, समावेशिता और भाईचारे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

इस अवसर पर जिला महामंत्री विनोद हर्ष, मधुसूदन शुक्ला, संतोष दास, वैभव सिंह देव, आरडी चौहान, राधा रवि, आशीष गुप्ता, कमलेश तिवारी, मनोज कंसारी सहित अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव-2026 में सूरजपुर की प्रतिभा का दम, खिलाड़ियों ने बढ़ाया जिले का मान

*** राज्यस्तरीय मंच पर जिले के खिलाड़ियों ने दर्ज कराई सशक्त उपस्थिति, युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत**

सूरजपुर, 04 अगस्त 2026 द शूटर। किसी भी जिले की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन युवाओं से भी बनती है जो अपने हुनर और मेहनत के दम पर बड़े मंचों तक पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव-2026 में सूरजपुर जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए यह साबित कर दिया कि जिले की खेल प्रतिभाएं भी अब राज्य स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में सूरजपुर जिले का प्रतिनिधित्व तीन खिलाड़ियों एवं खेल प्रतिनिधियों ने किया। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिले से वॉलीबॉल खेल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी सौरव साहू एवं अमीषा राजवाड़े (सूरजपुर एमेच्योर वॉलीबॉल संघ) तथा एथलेटिक्स की खिलाड़ी अंजु सिंह ने भाग लेकर जिले का गौरव बढ़ाया।

राज्यस्तरीय आयोजन में सहभागिता के दौरान खिलाड़ियों को खेलों के आधुनिक स्वरूप, नई संभावनाओं, खेल प्रबंधन और खिलाड़ियों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त हुई। यह अनुभव उनके खेल जीवन को नई दिशा देने के साथ ही भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी प्रेरणादायक साबित होगा।

जिले के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और नागरिकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सूरजपुर के लिए गर्व का क्षण बताया। उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे अवसर स्थानीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और जिले के अधिक से अधिक युवा खेलों को अपना कर प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आएंगे।

सरगुजा पुलिस को मिला नया नेतृत्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में रितेश चौधरी ने संभाली कमान

*** जनसेवा, प्रभावी कानून-व्यवस्था और सामुदायिक पुलिसिंग को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता**

अम्बिकापुर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। सरगुजा जिले की पुलिस व्यवस्था को मंगलवार को नया नेतृत्व मिला, जब राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारी रितेश चौधरी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। अपने पहले ही दिन उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि उनकी कार्यशैली का केंद्र आम नागरिकों का विश्वास, संवेदनशील पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना होगा। पदभार संभालने के बाद श्री चौधरी ने डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा आईपीएस राजेश अग्रवाल से सौजन्य भेंट कर जिले की वर्तमान कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जनसेवा तथा सामुदायिक पुलिसिंग की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले मार्गदर्शन को उन्होंने अपनी आगामी कार्ययोजना का आधार बताया।इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और शाखा प्रभारियों से परिचय प्राप्त करते हुए कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा हो, ताकि आमजन को पुलिस सेवाओं का लाभ बिना अनावश्यक विलंब के मिल सके।अपने संबोधन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रितेश चौधरी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता जितना मजबूत होगा, अपराध नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निराकरण किया जाएगा और पुलिस व्यवस्था को अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सरगुजा में पदस्थापना से पूर्व श्रीतेश चौधरी उप सेनानी, 14वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, धनौरा (जिला बालोद) के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव और अनुशासित कार्यशैली के लिए पहचाने जाने वाले श्री चौधरी के आगमन से जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा जनकेंद्रित स्वरूप मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुलमिलाकर नई जिम्मेदारी के साथ सरगुजा पुलिस महकमे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अब आमजन की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जनसेवा और सामुदायिक पुलिसिंग को प्राथमिकता देने की उनकी प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर किस तरह नई मिसाल कायम करती है।

दूर बसे गांवों के नौनिहालों तक पहुंचेगी विकास की नई किरण, सूरजपुर को मिले 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र

*** मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल लाई रंग, दूरस्थ गांवों की माताओं और नौनिहालों तक अब और आसानी से पहुंचेंगी पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं**

सूरजपुर 04 अगस्त 2026, द शूटर। गांव का हर बच्चा स्वस्थ रहे, हर मां को समय पर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और दूरस्थ बस्तियों तक भी शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में महिला एवं बाल विकास सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की विशेष पहल से सूरजपुर जिले को पांच नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिली है। इससे उन बस्तियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जहां अब तक ऐसी सुविधाओं की पहुंच सीमित थी।

दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरत को देखते हुए लिया गया निर्णय

महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निदेशों एवं राज्य शासन की स्वीकृति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों तक पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा जैसी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।

इन पांच स्थानों पर संचालित होंगे नए आंगनबाड़ी केंद्र

स्वीकृति के अनुसार ओड़गी एवं भैयाथान परियोजना के अंतर्गत डगमलापारा (चेंद्रा सेक्टर), भूंडा (मोहरसोप सेक्टर), झाड़ूडीह (चेंद्रा सेक्टर), पण्डोपारा (चेंद्रा

सेक्टर) तथा बगईहापारा (दरीपारा सेक्टर) में नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे। इन स्थानों का चयन स्थानीय आबादी, भौगोलिक स्थिति और जरूरतों का आकलन करने के बाद किया गया है।

युक्तियुक्तकरण से बढ़ेगी योजनाओं की प्रभावशीलता

विभाग ने यह भी तय किया है कि कुछ पहले से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और अधिक से अधिक हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा।

करीब 60 दिनों में शुरू होगा संचालन

संचालनालय ने जिला प्रशासन और संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी नवस्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करीब 60 दिनों के भीतर प्रारंभ किया जाए। साथ ही पोषण ट्रैकर एवं आईसीडीएस पोर्टल पर आवश्यक अद्यतन, कार्यकर्ता एवं सहायिका की व्यवस्था तथा भवन और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

'हर बच्चे तक पहुंचे बेहतर पोषण', सरकार की प्राथमिकता

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को सुपोषण, बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होने से दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले बच्चों और माताओं को सीधा लाभ मिलेगा तथा कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई मजबूती मिलेगी।

जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या होगी 2086

विभागीय जानकारी के अनुसार इन पांच नए केंद्रों की स्वीकृति के बाद सूरजपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 2086 हो जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच मजबूत करने तथा मातृ एवं शिशु कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एक महीने से जियो नेटवर्क बेपटरी, मोबाइल हाथ में फिर भी लोग अपनों और जरूरी सेवाओं से कटे

*** कॉलिंग ठप, इंटरनेट सुस्त, रिचार्ज की रकम हो रही बेअसर, समाधान की आस में क्षेत्रवासी**

रामानुजनगर, 04 अगस्त 2026, द शूटर। तकनीक के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क अब केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार, सरकारी सेवाओं और रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में रामानुजनगर क्षेत्र में जियो नेटवर्क की लगातार बिगड़ी व्यवस्था ने हजारों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले करीब एक महीने से क्षेत्र के लोग कॉलिंग और इंटरनेट की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उनका दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

क्षेत्र के कई गांवों में मोबाइल पर नेटवर्क के सिग्नल तक गायब हो जाते हैं। जहां नेटवर्क दिखाई देता भी है, वहां कॉल बार-बार कट जाती है, आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती या फिर कॉल ही नहीं लग पाती। इंटरनेट की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि सामान्य वेबसाइट खोलने, ऑनलाइन भुगतान करने या जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करने में भी काफी समय लग रहा है। कई बार इंटरनेट पूरी तरह बंद होने जैसी स्थिति बन जाती है।

इस समस्या का असर सबसे ज्यादा विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र नियमित रूप से कक्षाओं और अध्ययन सामग्री से जुड़ नहीं पा रहे हैं। किसान मौसम, फसल और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऑनलाइन जानकारी लेने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वहीं व्यापारी डिजिटल भुगतान बाधित होने से ग्राहकों और कारोबार दोनों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि जरूरी ऑनलाइन कार्यों के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाकर नेटवर्क तलाशना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि हर महीने वे समय पर रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप सेवा नहीं मिल रही। उनका आरोप है कि लगातार खराब नेटवर्क के कारण रिचार्ज की पूरी राशि व्यर्थ साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि कंपनी गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो प्रभावित अवधि के लिए रिचार्ज की वैधता बढ़ाने या उपभोक्ताओं को उचित राहत देने जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। इससे लोगों में कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि डिजिटल भारत की परिकल्पना तभी सफल होगी, जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरोसेमंद दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हों।

क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन, दूरसंचार विभाग तथा जियो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि नेटवर्क संबंधी तकनीकी खामियों की तत्काल जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाए। उनका कहना है कि आज मोबाइल नेटवर्क सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंकिंग और शासन की सेवाओं तक पहुंच का आधार बन चुका है। यदि जल्द ही स्थिति नहीं सुधरी तो उपभोक्ताओं का भरोसा टूटने के साथ-साथ उनका आक्रोश भी और बढ़ सकता है।

साहू समाज आईटी सेल में प्रवीण कुमार साहू को मिली प्रदेश कार्यकारी सदस्य की जिम्मेदारी, जिले में खुशी का माहौल

सूरजपुर, 04 अगस्त, द शूटर। सामाजिक संगठनों की मजबूती में युवाओं की सक्रिय भागीदारी आज समय की बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने अपनी आईटी सेल को और अधिक प्रभावी बनाने की पहल करते हुए सूरजपुर जिले के प्रवीण कुमार साहू को प्रदेश कार्यकारी सदस्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही जिले के साहू समाज के पदाधिकारियों, युवाओं और समाजजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू की अनुशंसा तथा आईटी सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू द्वारा जारी द्वितीय कार्यकारिणी सूची में प्रवीण कुमार साहू को यह दायित्व सौंपा गया है। संगठन ने उनके कार्यों, सक्रियता और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी दी है।

अपनी नियुक्ति पर प्रवीण कुमार

साहू ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और अधिक बढ़ाने वाला अवसर है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नीरेन्द्र साहू, प्रदेश संयोजक द्वारिका साहू, आईटी सेल प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी महामंत्री मनीष साहू तथा जिला अध्यक्ष राम लल्लू साहू का विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होंने कहा कि संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह दायित्व सौंपा है, उस विश्वास पर पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनका उद्देश्य डिजिटल माध्यमों के जरिए समाज की गतिविधियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, युवाओं को संगठन से जोड़ना तथा सामाजिक एकता और जागरूकता को मजबूत करना रहेगा।

प्रवीण कुमार साहू ने विश्वास जताया कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आईटी सेल समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, संगठन की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने और नई पीढ़ी को समाजहित के कार्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनकी नियुक्ति पर सूरजपुर जिला साहू समाज के पदाधिकारियों, युवा साथियों एवं शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन की डिजिटल गतिविधियों को नई गति और नई पहचान मिलेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- रूपेश दुबे द्वारा आर्यन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, पॉवर हाउस रोड नमना कला अम्बिकापुर, सरगुजा, छ0ग0 से मुद्रित एवं मेन रोड प्रतापपुर, खोरमा, जिला- सूरजपुर, छ0ग0 से प्रकाशित। संपादक- प्रवीण दुबे* (* समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। फोन- 07777271215